THE BOOK WAS DRENCHED

TEXT PROBLEM WITHIN THE BOOK ONLY

UNIVERSAL
LIBRARY
OU_186550
UNIVERSAL
LIBRARY

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर सम्मेलन ११, १२, १३, जून १९५५ की रिपोर्ट आपकी सेवा में प्रस्तुत है। प्रान्तीय सम्मेलन की वार्षिक रिपोर्ट के छपाने का यह प्रथम प्रयास है। साधनों की कमी और समयाभाव के कारण जिस प्रकार की रिपोर्ट होनी चाहिये थी वह यह न हो सकी। फिर भी प्रथम प्रयास होने के कारण त्रुटियों को क्षमा करेंगे।

यह रिपोर्ट साथी राम सागर मिश्र, संयुक्त मंत्री प्रजा सोशलिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश व साथी अध्यातम त्रिपाठी के अथक, परिश्रम के विना छपना असंभव था। मैं उनका आभारी हूँ।

रामचन्द्र शुक्ल
प्रान्तीय मंत्री
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
उत्तर प्रदेश

स्वागताध्यक्ष श्री दलशृंगार दुबे का भाषण

श्री दलशृंगार दुबे ने स्वागत भाषण करते हुए कहा कि अपने जिले की मुख्य नगरी गाजीपुर की पवित्र भूमि पर जिले की अकिंचन और साधनहीन परन्तु प्रबल भावनामयी जनता की ओर से आपके स्वागत का अवसर प्राप्त कर मैं अपने को धन्य और कृतकृत्य मानता हूँ।

यद्यपि हम आपके स्वागत और सुविधा के हेतु उपयुक्त सामग्री एकत्र कर सकने में सर्वथा असफल से हैं परन्तु मुझे पूर्ण बिश्वास है कि आप हमारी दुर्बलताओं, परिस्थिति की विवशताओं अन्ततोगत्वा अपनी उदारता से हमारी सफलता को भी सफलता के रूप में परिणत किये बिना नहीं रह सकते।

महानुभाव, हमारा गाजीपुर जिला दीर्घकाल से अपने ऐति-हासिक और भौगोलिक अवस्थाओं तथा पुण्य सलिला भगवती भागीरथी (गंगा) की धार से सिंचित होने के कारण पौराणिक, बौद्ध और मुगल काल से ही अपना एक विशेष स्थान रखता आया है।

प्राचीन काल में यमदग्नि-विश्वामित्र, स्कन्द गुप्त, चकवा. म॰ भाता आदि महापुरुषों की जन्म एवं कर्मभूमि होने का सौभाग्य इसे प्राप्त है।

गत ब्रिटिश काल में बिहार-केशरी स्वनाम धन्य 'बाबू कुंअर सिंह एवं उनके सहायकों के गुरिल्ला युद्ध को मुख्य भूमि होने का भी सौभाग्य इसे प्राप्त है।

स्वाधीनता-संग्राम की गांधी-परम्परा में भी यह जिला सन् १९२१, १९३०, १९३२ और १९४०, ४२ में देशों की अगली पंक्ति के २४ स्थानों में से एक माना गया है जिसे सभी राष्ट्र प्रेमी भली भांति जानते हैं।

यह जिला देश के घनी जन संख्या एवं उद्योगविहीन जिलों में मुख्य होने के कारण यहाँ के राष्ट्रीय कार्यकर्ता समाजवादी आंदोलन में भी आगे रहे हैं। इसी कारण यहाँ की कांग्रेस, सोशलिस्ट और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी देश में अपना विशिष्ट स्थान रखती आ रही है जिसके प्रमाण स्वरूप हमारा एक प्रतिनिधि दिल्ली की लोकसभा और ३ लखनऊ की विधानसभा में पहुँच पाये हैं।

भूतकाल के शासनों का बिद्रोही और उपेक्षित होने के कारण इस जिले की जनता को सुविधा और बिकास का अवसर कभो नहीं मिला।

आज का कांग्रेसी शासन भी दमन भ्रष्टाचार और जोर जुल्म को ही अपनी मर्यादा का साधन मानते हुए भी जनता के सहयोग की खोखली पुकार लगाने और उसके कर्मचारी कागजी खानापुरी करने में अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं।

इस जिले की पार्टी और उसके कार्यकर्ता जीवन की बाजी लगाकर भी सरकारी गैरसरकारी जोर जुल्म का विरोध करने और लोकमास में परिबर्तन लाने के लिए कृतसंकल्प और सतत् प्रयत्नशील हैं।

इस जिले की जनसंख्या लगभग ११।। लाख है इसके पास मुख्य जीविका का साधन खेती ही है। प्रति व्यक्ति जोत की भूमि १ बीघे से भीं कम है, उस पर भी यहाँ कुछ कथित जन नेता ऐसे हैं जो हजार पांच सौ बीघे भूमि पर उचित अनुचित अधिकार रखते हैं।

सरकारी कागजों में जाल करने कराने में भी कसर नहीं रखते और अब थोड़े दिनों से समाज परिबर्तन का साधन बनने

का नारा भी लगाना आरम्भ कर दिया है ऐसे लोग सर्वसाधारण को मूर्ख और अन्धा समझ अपने कुकृत्यों पर परदा डालते तथा, राजपुरुषों और कर्मचारियों के कृपापात्र बन कर और यथास्थिति बनाये रखने का प्रत्येक सम्भव उपाय काम में लाते चले जा रहे हैं।

अब हम लोगों को लोकमास में परिवर्तन लाकर तथा अपने अधिकारों की प्राप्ति और रक्षा के लिए शान्तिमय वर्ग-संघर्ष को तेज कर ही इस दुःखद स्थिति का अन्त करना पड़ेगा नहीं तो बेकारों की अपार सेना हमें हमारे समाज और इस कपटाचारी सरकार का भी बुरी तरह अन्त करके ही दम लेगी।

राष्ट्रीय एवं सामाजिक समस्याओं की उलझनों के समय हमारा गाजीपुर जिला और यहाँ के समाजवादी कार्यकर्ता दिशा को मोड़ने में बराबर सहायक रहे हैं आज भी जब समाजवादी परिवर्तन और समाजवादी आन्दोलन को एक विशेष मोड की आवश्यकता है जिसके लिए जनता आहें भरती और उल्टी सांस ले रही है, हम आशा करते हैं कि अपने इस सम्मेलन में इसी भूमि पर समाजवादी आन्दोलन को ऐसा मोड़ देंगे जिससे अस्पष्टता उदासीनता और अकर्मण्यता का अन्त होकर आत्म-विश्वास, साहस और विवेक भरी ज्योति जगेगी और जनता संघटित होकर हमारे साथ अपने मंजिल पर पहुंच कर राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक शोषण का अन्तकर वर्गहीन समाजवादी समाज की स्थापना करके दम लेगी, जिस समाज में प्रत्येक के लिए उचित काम दाम और आराम की व्यवस्था रहे।

हमारे देश के कतिपय विचारक यह कहते सुने जा रहे हैं कि हृदय का परिवर्तन हुए बिना कानून से यथार्थ लाभ नही

हो सकता. उनसे भी मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जड़ता कट्टरता और यथास्थिति का परिवर्तन कानून से हो जाने के पश्चात् ही हृदय परिवर्तन भी सम्भव है। अतः जनता को कानूनी परिवर्तन चाहने से विमुख करने उदासीन रहने का कोरा उपदेश छोड़ कर लोक मानस के परिवर्तन में सक्रिय सहयोग देने के लिए शान्तिमय संघर्ष की तैयारी करें समय की यही पुकार है।

सफल समाजवादी क्रांति से पहले हमारे जिले की कुछ तात्कालिक समस्याएँ हैं जिनकी ओर मैं सम्मेलन, सरकार और समाज का ध्यान आकृष्ट कर देना आवश्यक समझता हूँ।

१—गंगा नदी पर एक पक्का पुल।

२—गाजीपुर शहर में एक डिग्री कालेज।

३—गाजीपुर जिले से बिलग हुए महाइच परगने को जमामिया तहसील में मिलाकर संतुलन ठीक करना।

४—अनेकों गृह उद्योग चीनी और काच उद्योग एवं अफीम से बनने वाली औषधि उद्योग आदि की व्यवस्था।

५—हमारे गुलाब तथा चमेली और उनसे बने इत्र और तेल के कारबार को इसलिये धक्का लगा है कि जनता की निर्धनता के कारण खरीदने की शक्ति घट गयी है, इसे भी पूरा करना है।

६—खेती के सामान की सस्ती और खान एवं कारखाने के माल की महंगी से किसान तथा छोटा दूकानदार बर्बाद हो रहा है मूल्य संतुलन कर इसे बचाना है।

मैंने आवश्यकता से कदाचित अधिक समय लिया, आशा है आप इसे क्षमा करेंगे। हमारे गाजीपुर में अफीम की

मादकता और गुलाब की मोहकता दोनों ही विद्यमान हैं। हमारा गुलाब ही आपको प्रभावित करने में समर्थ होगा। अन्त में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ। आशा है आप त्रुटियों को क्षमा करेंगे।

साथी मधुलिमये-एशियन सोशलिस्ट कांफरेन्स व प्रजा सोशलिस्ट पार्टी व सोशलिस्ट पार्टी के भूतपूर्व संयुक्त मंत्री के उद्‌घाटन भाषण का सारांश

समाजवादी दल के सत्तारूढ़ व्यक्तियों के अवैध तथा अनाधिकारिक कार्यों से समाजवादी दल का भविष्य अँधकार पूर्ण हो गया है। दल के समक्ष बहुत ही सरल प्रश्न सह-असस्तित्व अथवा सर्वनाश का था। मुअत्तल का सिलसिला जारी कर कार्य समिति ने विनाश का पथ ही अपनाया है। किन्तु कोई भी समाजवादी इसे चुप चाप सहन नहीं करेगा। इस आंदोलन को अब दलदल से बाहर निकालने का भार हम लोगों पर ही है।

भारतीय समाजवादी दल अब से पहले ३ अवस्थाओं—कांग्रेस समाजवादी दल समाजवादी दल तथा प्रजा समाजवादी दल से गुजरा है। इससे दल का वर्तमान रूप भी रहेगा अथवा नहीं इसकी चिन्ता नहीं। आवश्यक प्रश्न तो यह है कि नव-समाज के लिए जिस संघर्ष तथा खोज से सभी अवस्थाओं में सक्रिय समाजवादियों को प्रेरणा मिलती रही है, वह नवशक्ति तथा संकल्प के साथ आज भी जारी है।

इसके बाद श्री लिमये ने आंध्र के निर्वाचन, मणिपुर के संघर्ष तथा गोवा आंदोलन सम्बन्धी सत्तारूढ़ दल की नीति का

जिक्र करते हुए कहा कि शासक दल ने यह फरमान भी निकाला कि समाजवादी युवक सभा सम्मेलन में इसलिए कोई प्रजा समाजवादी भाग न ले क्योंकि उसकी अध्यक्षता मुअत्तल सदस्य करने वाले थे। दल ने एक गश्ती चिट्ठी में यह मांग की कि प्रजा समाजवादी दल की सब से बड़ी शाखा के अध्यक्ष मुअत्तल किये जायं। इन सबसे यह स्पष्ट हो रहा है कि दल के भीतर तानाशाही प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है।

वस्तु स्थिति यह है कि गत वर्ष इन्दौर में जो विधान स्वीकृत हुआ उसके अन्तर्गत बम्बई की समिति का स्थान एक जिले को समिति-सा हो गया है। अत: किसी सदस्य को मुअत्तल करने का उसे कोई अधिकार नही है। इसके सिवा मेरे विरुद्ध काररवाई करने की जो दलील दी गयी है वह बिलकुल लचर है। सार्वजनिक चन्दे के गबन और नकली सदस्यता आदि सम्बन्धी एक धारा का अर्थ कार्य समिति के निर्णयों की सभी प्रकार की आलोचनाओं पर प्रतिबन्ध के रूप में है। वह बिलकुल ही विचित्र है, विशेषकर तब जब यह स्मरण किया जाता है कि बम्बई की समिति ने तिरुवांकुर-कोचीन के निर्वाचन सम्बन्धी समझौते तथा मोरे के साथ संसदीय दल बनाने के लिये महाराष्ट्रीय शाखा की अनुमति के लिए कार्य समिति के निर्णयों को खुले आम आलोचना की। अदालत में कार्यसमिति के इन सभी निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है परन्तु साधारणतया राजनीति वाले ऐसा नहीं करते। अत. साधारण मार्ग यही है कि कार्य समिति की ज्यादती के विरुद्ध देश भर में विद्रोह बढ़ने दिया जाय।

श्री लिमये ने बताया कि भारत धीरे-धीरे एक दलीय राज्य की दिशा में बढ़ रहा है। सर्वोदयवादियों, नेहरू सरकार तथा

कम्युनिस्टों के रुख से यह स्पष्ट हो रहा है। न तो प्रथम पंच-वर्षीय योजना से बेकारी, गरीबी असमानता दूर हुई है और न तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से ही होगी। प्रथम योजना से आर्थिक व्यवस्था के केन्द्रीयकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है और दूसरी तीसरी से यह काम अच्छी तरह से पूरा हो जायगा। इससे करोड़ों पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, तथा चतुर्दिक सामाजिक अराजकता तथा तनातनी फैलेगी।

अतः एक ऐसे दल की आवश्यकता है जिसका ध्येय विकेन्द्रीकरण तथा समाजवादी कार्यक्रम हो तथा जो पीड़ितों के पक्ष का समर्थन करे। हमें यह दल बनाना है, भले ही उसके लिए कुछ भी मूल्य क्यों न देना पड़े। इस समय निम्नलिखित ढंग के काय होने चाहिये—

१—रचनात्मक कार्य, सामाजिक सुधार तथा सैद्धांतिक शिक्षण के आधार पर समाजवादी युवक संघटन की ओर सर्वाधिक ध्यान दिया जाय।

२—छटनी तथा कानपुर की भांति अधिक काम के विरुद्ध मजदूरों का संघर्ष हो।

३ बढ़ती हुई बेकारी के विरुद्ध शिक्षित युवकों में आंदोलन किया जाय।

४—गल्ले के गिरते हुए मूल्य तथा समानता के विरुद्ध आंदोलन हो।

५—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अनुचित कर‌भार का प्रबल बिरोध किया जाय।

६—स्थानीय संस्थाओं को और अधिकार देने का आंदोलन हो।

अन्त में गोवा आंदोलन के सम्बन्ध में मैं एक शब्द कह देना चाहता हूँ। आंदोलन के प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में चलते रहने का खतरा है। किन्तु इसे सच्चे जनवादी आंदोलन का रूप देने की आवश्कता है।

श्री गोपालनारायण का अध्यक्षीय भाषण

हम लोग यहाँ बर्बरतापूर्ण दण्ड की छाया में एकत्र हुए हैं। २५ सदस्यों की समिति ने भूत भगाने जैसा आधारण उत्साह दिखा कर तीस हजार से अधिक प्रजा समाजवादी दल के सदस्यों के सैकड़ों प्रतिनिधियों के सम्मेलन पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इस अवैधानिक महापराध के कारण ही इस सम्मेलन की अध्यक्षता के सम्बन्ध में मेरे मन में जो झिझक थी वह समाप्त हुई। यदि मेरे विरुद्ध मुअत्तली की कारवाई न की गयी होती तो मैं अध्यक्षता से विरत रहता। यहाँ इस सम्मेलन में एकत्र होकर आप लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी आंदोलन में आन्तरिक्त या वाह्य अन्याय का प्रतिरोध करने की क्षमता अभी वर्तमान है।

कुछ लोगों ने कहा है कि सैद्धान्तिक मतभेद का नारा बुलन्द कर अनुशासन भंग के कार्यों को छिपाया जा रहा है। इसके उत्तर में मेरा यह निवेदन है कि अनुशासन भंग के झूठे नारे

को बुलन्द कर सैद्धन्तिक तथा नीतिगत मतभेद को छिपाने का प्रयत्न किया जा रहा है। सारा देश सैद्धान्तिक मतभेद की बात जानता है अतः सैद्धान्तिक मतभेद से इनकार करना इन लोगों के लिए सम्भव नहीं। अनुशासन के नाम पर अवाञ्छत व्यक्तियों से पिंड छुड़ाने की चेष्टा की गयी।

अनुशासन का अर्थ

आपने आगे कहा कि प्रश्न यह उठता है कि वस्तुतः अनुशासन है क्या? अनुशासन विचार विशेष के प्रचार प्रसार के लिए संस्था क संघटन का साधन है अथवा संस्था के अधिकारियों के अधिकार रक्षा के हेतु विरोधियों की वाणी अवरुद्ध करने का साधन है। मेरे विचार से राजनीतिक दलों का जहाँ तक सम्बन्ध है अनुशासन का विधेयात्मक और निषेधात्मक (भला बुरा) दोनों ही पहलू रहता है। अनुशासन के विधायक उपयोग से किसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिये आवश्यक नियमों के पालन और कार्यों के करने की व्यवस्था होती है।

अनुशासन के दुरुपयोग अथवा निषेधात्मक उपयोग से पार्टी की प्रगति रुक जाती है। उसके लक्ष्यों की पूर्ति अवरुद्ध हो जाती है तथा दूसरी पार्टियों की उसके मुकाबले बन आती है। इस प्रकार यह आसानी से समझा जा सकता है कि प्रजा-समाजवादी दल में वस्तुतः किसने अनुशासन भंग किया है।

लोकतन्त्र का आधार

इसके अतिरिक्त संस्थाओं और आन्तरिक सम्बन्धों उनके अधिकारों और कार्यों की सीमा तथा कार्य पद्धति के सम्बन्ध

में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। गलत तरीके से नौकरी से निकाल देने पर नौकर भी मालिक के विरुद्ध दावा दायर कर सकता है। किसी संस्था के अधीन समितियों तथा नेतृबृन्द के अधीनस्थ व्यक्तियों को कभी यह नहीं समझना चाहिये कि मुख्य संस्था और प्रमुख नेता उसके साथ मनमाने व्यवहार अथवा उनके विरुद्ध मनमानी कारवाई कर सकते हैं।

संस्था अथवा पार्टी की सर्वोच्च समिति तथा दल के सर्वोच्च नेता स्वीकृत नियमों के अन्तर्गत तथा अपनी अधिकार सीमा में ही कार्य करें। यही लोकतन्त्र की मौलिकता है। यही उसका आधार है। लोकतन्त्र में बहुमत मनमाना कार्य करने को सार्वभौम स्वतन्त्र है। जब किसी भी लोकतांत्रिक संस्था की सर्वोच्च समिति अधीन समितियों के सम्बन्ध में एक पक्षीय निर्णय करती है तथा अपनी अधिकार सीमा का उल्लंघन करती है तो लोकतन्त्र की रक्षा के लिए उसके कार्यों को चुनौती देना अनिवार्य हो जाता है। भारतवर्ष में यह और भी आवश्यक है, क्योंकि नेतृबृन्द छोटी समितियों को पटवारियों की समिति समझते हैं। इस समय प्रजासमाजवादी दल में जो संघर्ष छिड़ा हुआ है उसमें हमारी विजय का अर्थ भारतीय जनता का न्यायपूर्ण राजनीतिक विजय है।

दूसरा प्रश्न है अपराध और दण्ड का। प्राचीन भारत में चोरी के अपराध में लोगों के हाथ काट लिये जाते थे। आज भी कुछ लोग वैसा ही करने को सोच सकते हैं पर कोई बिवेकवान प्राणी इसे भयंकर अमानुषिकता और अपमान समझ सकता है। किसी भी व्यक्ति को भाषण के लिए बुलाना कोई अपराध नहीं है मुअत्तल सदस्य को बोलने का अधिकार तो है ही,

यद्यपि सफाई देने का उनका अधिकार छीन लिया गया । यदि कुछ लोग किसी को (श्री लिमये को) भाषण के लिए बुलाने के कार्य को अपराध समझते हैं तो भी यह ऐसा भयंकर अपराध नहीं है कि मृत्युदण्ड जैसी सजा दी जाय। ऐसा करना बर्बरता-पूर्ण है।

अब मैं संक्षेप में अधिकारारूढ़ दल से अपने सम्बन्ध के सम्बन्ध में कुछ कहूँगा। पार्टी में तथा उसके बाहर इस प्रश्न पर बहुत विस्तार से विचार किया गया है। पर अभी तक इस प्रश्न को लोग जीवित ही रखे हैं।

बार-बार यह घोषणा की गयी कि पार्टी का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में न जायगा पर कांग्रेस में लोग चले जा रहे हैं। अब तक किसी ने इस बारे में कुछ कहा नहीं है।

वास्तविक प्रश्न निकट अथवा सुदूर भविष्य में कांग्रेस से सहयोग अथवा असहयोग का नहीं है। वास्तविक प्रश्न तो विरोधी पार्टियों के कार्य और व्यवहार का है। भविष्य में विरोधी पार्टियाँ क्या कहेंगी यह गौण प्रश्न है, वर्तमन में वे क्या कर रही हैं यही मुख्य प्रश्न है। आज भारत की सभी विरोधी पार्टियाँ बड़े प्रश्नों पर मौन रहती हैं पर छोटे छोटे प्रश्नों पर सरकार की आलोचना करती हैं।

इस प्रकार विरोधी दल केवल दिखाई देता है। मैं चाहता हूँ कि प्रजासमाजवादी दल संसद या विधानसभाओं में बड़े बड़े प्रश्नों पर मौन न रहे वरन् वह बेकारी, कृषि उत्पादनों के मूल्य में गिरावट, नागरिक अधिकार आदि प्रश्नों पर ऐसी जबर्दस्त आवाज बुलन्द करें कि जनता और सरकार का ध्यान

उस ओर आकृष्ट हो। आज देश में कोई भी वास्तविक विरोधी दल नहीं है। अतः उत्तर प्रदेश में हम लोग प्रजासमाजवादी दल को ऐसे संघटन का रूप प्रदान करना चाहते हैं जो सरकार से बाहर रहने पर वास्तविक विरोधी दल का काम करे तथा सरकार बनाने पर देश को समाजवाद की ओर ले चले।

संसद् और विधान सभाओं में विरोधी दल ऐसा होना चाहिये जो जनता के दुःखों और आकांक्षाओं को ध्वनित और प्रतिबिम्बित कर सके। आज संसद् और विधान सभाएं निर्जीव सी हैं। रक्तहीन हैं। उन्हें वही दल जीवन प्रदान कर सकता है जिसका नेतृत्व अधिकारारूढ़ दल से बंधा नहीं है। आज पार्टी का नेतृत्व जान बूझ कर या अनजान में देश के मुख्य प्रश्नों की अपेक्षा कर रहा है।

राष्ट्रीय कार्य समिति के वर्तमान कार्यों से समस्त देश के सौ दो सौ समाजमादी विधान मण्डलों में चले जायेंगे। कुछ को मन्त्रिमण्डलों में स्थान मिल जायगा। यह सब कुछ देश के पुनर्निर्माण में सहयोग के नाम पर होगा। क्या हम लोग १००, २००, नेताओं तक ही सीमित हैं या हम जनता की पार्टी हैं जिसका उद्देश्य देश का कायाकल्प करना है।

इन सब बातों के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर लेने पर ही समाजवादी आन्दोलन का भविष्य निर्भर है। प्रजा-समाजवादी दल अपना स्वरूप स्थिर करने के बाद कांग्रेस के कुशासन की आलोचना करने तथा देशव्यापी आंदोलन करने में सक्षम हो सकेगा। तभी योग्य व्यक्ति विधान मंडलों तथा उत्तरदायित्व के पदों पर पहुंच सकते हैं।

शोक प्रस्ताव

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन श्री रामनरेश सिह की असामयिक मृत्यु पर हार्दिक शोक प्रगट करता है। रामनरेश सिंह जी की जो देन समाजवाद के आन्दोलन में है, वह चिरस्मरणीय रहेगा। इस समय जब कि समाजवादी आन्दोलन को उग्र बनाने के लिये उनकी आवश्यकता थी एकाएक हमारे बीच से उठ जाना, बहुत धक्का पहुँचाता है। सम्मेलन उनके परिवार के प्रति समवेदना प्रगट करता है।

यह सम्मेलन मशहूर मजदूर नेता श्री एन० एम० जोशी तथा मुनिराज सिंह (जौनपुर) की असामयिक मृत्यु पर शोक प्रगट करता है और इनके परिवार के प्रति अपनी समवेदना प्रगट करता है।

प्रान्तीय मन्त्री की रिपोर्ट

वस्तुतः इस रिपोर्ट को हमारे बुजुर्ग रहनुमा तथा निगोहां सम्मेलन में चुने गये प्रान्तीय मन्त्री साथी रामनरेश सिंह को पेश करनी थी किन्तु हम लोगों के दुर्भाग्य से अब वे हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन के बाद जनवरी के अन्त में मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी गई। इसमें मैं संक्षेप में, जो गत वर्ष में काम हुआ, उसकी रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा।

संगठन

सूबे में ५१ जिले हैं। इसमें केवल टेहरी गढ़वाल को छोड़कर अन्य सभी जिलों में पार्टी की शाखाएं काम कर रही थीं। किन्तु इधर आगरा शहर, इलाहाबाद जिला, बदायूं, एटा, गढ़वाल, लखीमपुर, पीलीभीत जिले के साथी प्रान्तीय कार्यालय को यह भी सूचना नहीं दिये कि इन स्थानों पर पार्टी के कितने सदस्य बने है। हालांकि इन स्थानों में से कुछ जगहों पर पार्टी की अच्छी शक्ति है। बाकी सभी स्थानों में पार्टी की शाखाएं काम कर रही हैं।

पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने के लिये कई प्रयत्न प्रान्तीय कार्यकारिणी की ओर से किये गये किन्तु वे कामयाब न हो सके। सर्वश्री काशी नाथ मिश्र, जीयाराम पालीवाल तथा वीरेन्द्र बहादुर सिंह जोनल इंचार्ज बनाये गये किन्तु काशीनाथ मिश्र के अलावा और किसी साथी ने अधिक काम नहीं किया। साथी जीयाराम पालीवाल ने कुछ काम किया किन्तु मेरठ में वे गिरफतार कर लिये गये और काशीनाथ जी मिर्जापुर में गिरफतार हो गये इस वजह से इन साथियों ने काम अधिक नहीं किया। वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी रूस चले गये थे और रूस से वापस लौटने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया।

प्रान्तीय कार्यकर्ता कैम्प

१२ मार्च से प्रतापगढ़ में प्रान्त के कार्यकर्ताओं का एक कैम्प हुआ। इस कैम्प में बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, जौनपुर, बनारस, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, फैजाबाद, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर, बांदा, फर्रुखाबाद, एटा, बदायूँ, सीतापुर, गोंडा, नैनीताल, अलमोड़ा, सहारनपुर, बुलन्दशहर आदि २७ जिले के २०० कार्यकर्ताओं ने भाग

लिया। डा० राममनोहर लोहिया, स्वामी भगवान, गोपाल नारायण सक्सेना, राजनारायण. रामचन्द्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही, ओंकार शरद, एस० के० रजमी एम० पी० आदि ने शिक्षक के रूप में भाग लिया।

पार्टी सदस्यता

इस वर्ष प्रान्त में कुल १, ४०, ८६० सदस्यता के फार्म विभिन्न जिलों को वितरित किये गये। इसमें ४०, ६५४ सदस्यों की सूची प्रान्तीय कार्यालय में आ चुकी है और १२६७ सदस्यों की सूची नहीं आई है। इस वर्ष कुल १३०० सक्रिय सदस्य बने हे। इनका ब्योरा नीचे दिया जा रहा है।

	नाम जिला	साधारण सदस्य	सक्रिय सदस्य
१.	आगरा जिला	७४४	—
२.	आगरा शहर	—	—
३.	अलीगढ़	७४७	२१
४.	अलमोड़ा	१८५	६
५.	आजमगढ़	१६२५	--
६.	इलाहाबाद जिला	—	—
७.	इलाहाबाद शहर	४५७	३०
८.	बहराइच	३८	१
९.	बाराबंकी	१५६३	२०
१०.	बांदा	१७४	—
११.	बलिया	१७४६	६५
१२.	बरेली	१२६१	२२
१३.	बस्ती	१६३४	५६
१४.	बनारस जिला	२५६४	८५

१५.	बनारस शहर	६५३	४३
१६.	बिजनौर	३०	—
१७.	बुलन्दशहर	६६१	४५
१८.	बदायूँ	—	—
१९.	देहरादून	७४	—
२०.	देवरिया	३६२२	—
२१.	एटा	—	—
२२.	इटावा	१,७७	५२
२३.	फरुखाबाद	१४५०	१३
२४.	फैजाबाद	११२२	५०
२५.	फतेहपुर	२३५	२५
२६.	गोंडा	४७३	१४
२७.	गोरखपुर	१०५६	१६
२८.	गढ़वाल	—	—
२९.	गाजीपुर	१८२४	१२०
३०.	हरदोई	—	—
३१.	हमीरपुर	—	—
३२.	जालौन	—	—
३३.	झांसी	५६	६
३४.	जौनपुर	१३५१	४७
३५.	कानपुर जिला	२६५८	१२४
३६.	कानपुर शहर	२३२६	१८५
३७.	लखीमपुर खीरी	—	—
३८.	लखनऊ जिला	२५२	५
३९.	लखनऊ शहर	४३३	.
४०.	मैनपुरी	२३१	१०

४१.	मेरठ	—	—
४२.	मिर्जापुर	४७२	३१
४३.	मुरादाबाद	९१	—
४४.	मुजफ्फरनगर	११५	२३
४५.	मथुरा	१०६४	६१
४६.	नैनीताल	२८०	६
४७.	प्रतापगढ़	२०२३	८१
४८.	पीलीभीत	—	—
४९.	रायबरेली	३१५	—
५०.	रामपुर	—	—
५१.	सहारनपुर	६४०	—
५२.	शाहजहाँपुर	७३०	—
५३.	सीतापुर	६४६	६
५४.	सुल्तानपुर	५०२	२४
५५	उन्नाव	२५८	—

इस प्रकार कुल सदस्यता ४०,९५४ हुई। किन्तु मेरठ से २५० रु०, हरदोई से २ रु० ८ आना, हमीरपुर से २५० रु०, उरई से ५० रु० तथा रामपुर से ८३ रु० ११ आ० सदस्यता शुल्क आया है और उनकी सूची नहीं प्राप्त हुई है। इस प्रकार कुल सदस्यता प्राप्त सूची तथा अप्राप्त सूची के अनुसार ४०,९५४+१२७२ अप्राप्त सूची को मिलाकर ४२,२२६ हुई।

सदस्यों का प्रान्तीय तथा केन्द्रीय कोटा २१,११३ रु० होता है किन्तु १५,०८३ रु० ७ आना ही प्राप्त हुआ है इस प्रकार ६,०४८ रु० जिलों के ऊपर बकाया है।

पार्लियामेन्टरी कार्य—

१ मार्च १९५४ से ३१ मई १९५५ के बीच में ६ असेम्बली

तथा ५ लोक सभा की सीटों का उपचुनाव हुआ। इसमें असेम्बली की ६ सीटों में ५ पर पार्टी के उमीदवार खड़े किये गये और उनमें से २ सीटें पार्टी को प्राप्त हुईं। पार्लियामेन्ट की ५ सीटों में से ४ पर पार्टी चुनाव लड़ी और १ पर कामयाबी हुई। इन सभी उपचुनावों को लड़ने के लिये प्रान्तीय पार्टी ने समुचित चुनाव संगठन तथा कार्यकर्ताओं का प्रबन्ध किया था।

विधान सभा का कार्य—

इस समय विधान सभा में २३ पार्टी के सदस्य तथा २ विधान परिषद् में हैं। इस अवधि में विधान सभा में विरोधी दल ने कई ऐतिहासिक कदम उठाये। और पूर्ववत् अपनी लड़ाकू नीति के अनुसार सरकार का मुंहतोड़ जवाब देती रही है।

आन्दोलन तथा सत्याग्रह

सिंचाई रेट वृद्धि विरोधी सत्याग्रह

प्रान्त में बढ़े हुए नहर रेट के विरुद्ध जो प्रचार और आन्दोलन पहिले से किया गया था उसको साकार रूप इटावा में साथी अर्जुन सिंह भदौरिया के नेतृत्व में २६ फरवरी से प्रारम्भ हुआ। उसके बाद मिर्जापुर में ५ मार्च से और सारे प्रान्त में १५ मई से सत्याग्रह चालू हो गया। अभी प्रान्त भर में प्रायः १००० सत्याग्रही गिरफ्तार हुए थे कि डा० राममनोहर लोहिया इस प्रान्त में दौरा करते हुए ३ जुलाई को फरुखाबाद में गिरफ्तार कर लिये गये। उसके बाद ही फरूखाबाद चलो का नारा लगा क्योंकि तब तक प्रायः सभी जिलों में गिरफतारियां बन्द हो गई थीं। आदेश होने की देर थी कि सारे प्रान्त और देश का ध्यान फरुखाबाद की ओर आकर्षित हुआ और देखते-देखते लगभग ३००० सत्याग्रही गिरफ्तार हो

गये। डा० लोहिया का मुकदमा इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुआ और उसमें उनकी ऐतिहासिक वकालत और साथी सतीशचन्द्र खरे के कानूनी सलाह के कारण पार्टी की विजय हुई और पहिले पहल इतिहास में सरकारी जजों ने भारतीय जनता को सिविल नाफर मानी का हक दिया। और स्पेशल पावर्स ऐक्ट १६३२ अवैधानिक घोषित किया गया। जिसके फलस्वरूप २७ अगस्त को सभी सत्याग्रही अपने अपने जेलों से विजय नाद करते हुए अपने अपने जिलों को वापस लौटे।

इस सत्याग्रह के दौरान में करदाया, भुड़कुड़ा, तिजिलापुर कोसी तथा अन्य स्थानों पर पुलिस ने जो पशुता का नंगा नाच किया है वह अद्वितीय है।

कुली आन्दोलन

लखनऊ में चारबाग स्टेशन पर वहाँ के ८०० कुलियों ने बेगार के विरुद्ध आन्दोलन किया। वहाँ ठेकेदार प्रतिदिन १५६ आदमियों से बेगार लेता है और उसके विरुद्ध आन्दोलन चल रहा था। २६ मार्च को पुलिस ने जी० आर० पी० थाने के अन्दर साथी चन्द्रिका सिंह करुणेश, अध्यात्म त्रिपाठी, जगदीश सिंह आदि के साथ-साथ और कुलियों को लाठी बूटों और ठोकरों से मारकर बेहोश कर दिया तथा उसके साथ ही २०६ कुलियों को गिरफतार किया।

कानपुर हड़ताल

कानपुर की सूती मिलों में रेशनालाइजेशन के खिलाफ वहाँ के मजदूर २ मई से हड़ताल कर रहे हैं। सरकार अपनी हठवादिता पर रुकी हुई है और मजदूर भी शान्तिमय तरीके से आन्दोलन चला रहे हैं और सभी मजदूर हड़ताल पर हैं।

सांस्कृतिक मोर्चा

मोर्चे के इंचार्ज श्री शमसी मीनाई प्रान्त के जिलों का दौड़ा करके नए शायरों और कवियों को पार्टी के नजदीक लाने में सफल हुये।

हिन्द किसान पंचायत ने गन्ना आन्दोलन के बाद नहर-रेट आन्दोलन में पार्टी के साथ पूरा सहयोग किया।

समाज वादी युवक सभा विद्यार्थियों में शिक्षण शिविर आदि के द्वारा समाजवादी विचार धारा फैलाने में काफी उद्योग रत रही। नहरेट आन्दोलन के समय २३ अगस्त १६५४ को विधान-सभा की गैलरी से प्रदर्शन करके स.यु.स. ने सरदार भगत सिंह की क्रान्तिकारी परंपरा को जनतांत्रिक रूप दिया।

हिन्द मजदूर सभा का कोई संगठित कार्य इस वर्ष विशेष रूप से न किया जा सका। कानपुर के सूती मिल मजदूरों की ऐतिहासिक हड़ताल सभा के नेतृत्व में ही चल रही है। मजदूर आन्दोलन को संगठित करने में ही कार्य कर्ता व्यस्त रहे। कानपुर के सूती मिल मजदूरों की ऐतिहासिक हड़ताल सभाके नेतृत्व में ही चल रही है।

आय व्यय का व्योरा १ जनवरी १९५४ से ३१ दिसम्बर १९५४ तक

आमदनी				खर्च			
पिछली रोकड़	२१९	७	०	अलाउन्स	४८९३	७	०
बैंक बैलेंस	२२३	१०	०	सफर खर्च	१९२६	१५	०
प्रतिनिधि शुल्क	५४२	०	०	डाक तथा तार	८०७	१०	३
फार्म छपाई दाम	६६४	३	०	स्टेशनरी	४४०	८	६
विधान सभा के सदस्यों से	२३४८	८	८	समाचार पत्र	२३७	१२	०
अन्य दान	१०६६	६	०	टेलीफोन तथा ट्रंक	३११	२	०
लोहिया अपील फंड	१०७	१२	०	फुटकर खर्च	४५७	१२	०
मेम्बरी फीस	३७५४	१२	०	फार्म की छपाई	७२४	८	०
अन्य आमदनी	२२०	३	०	सम्मेलन की छपाई	२८४	४	०
पेशगी की वापसी	०	०	०	सांस्कृतिक मोर्चा	२५	१	६

आमदनी				खर्च			
दुगलदेव पांडे	१०	०	०	प्रकाशन	१४	०	०
रामचन्द्र शुक्ल	८३८	१५	०	प्रकाशन केन्द्रीय पार्टी	११	४	०
संघर्ष	८१५	१५	०	मेहमानों के लिए	१२०	६	३
ब्रजकिशोर शास्त्री	३२	५	०	युवक मोर्चा	१२२	९	०
अध्यात्म त्रिपाठी	५६	६	९	मजदूर मोर्चा	३०	०	०
क्रेडिट बैलेंस	०	०	०	सहायता	२६९	४	०
संघर्ष	२५९	११	०	समाजवादी युवक सभा	२५	०	०
ईश्वरी सिंह	५	९	०	एडवान्स (पेशगी)	०	०	०
कर्ज की अदायगी	०	०	०	शर्मा होटल	१०५	०	०
गोपाल नारायण सक्सेना	४६५	४	६	च० सिं० करुणेश	४९	२	०
कोषाध्यक्ष वि० सभा	५५	०	०	ओम्प्रकाश दीपक	१०	०	०
राजनारायण	७	७	०	रामसागर मिश्र	५०	१४	०
पा० कमिटी	३६६	०	०	काशीनाथ मिश्र	५५	१४	०
सत्याग्रह सहायता कोष	१४४१	१५	०	माडर्न प्रिंटर्स	२०	०	०
				अर्जुनसिंह भदौरिया	१४	४	०
	१३७०१	८	३	जमुना प्रसाद बांदा	२४	०	०

आमदनी				खर्च			
				रामनरेश सिंह	१	२	६
				पा० कमिटी	१०११	८	६
रीटेन आफ	५०२३	५	३	सत्याग्रह खर्च	१४५६	१४	०
				फरीद अन्सारी	३	१५	६
				गन्ना समिति को सहायता	३	१०	०
					१३५४४	१०	६
				रीटेन आफ	५०२३	५	३
					१८५६८	०	०
				रोकड़ बाकी	१५६	१३	६
	१८७२४	१३	६		१८७२४	१३	६

एस० डी० बनर्जी	अध्यात्म त्रिपाठी	रामचन्द्र शुक्ल	देवकरण सिंह
एकाउन्टेन्ट	का० मन्त्री	मन्त्री	आडिटर

प्रान्तीय कार्यकारिणी का फैसला और गाजीपुर सम्मेलन

पार्टी रीति-नीति तथा संगठन और अनुशासन को लेकर पार्टी के अन्दर वाद विवाद खड़ा हुआ है। यों तो यह वाद विवाद नेहरू जय प्रकाश समझौता वार्ता से शुरू होकर .बेतूल सम्मेलन, फिर इलाहाबाद सम्मेलन तक चला। इलाहाबाद में पार्टी रीति नीति तय हुई। मगर कुछ व्यक्ति विशेष पार्टी तथा कांग्रेस के साथ समझौता करके चलने की नीति में विश्वास करते थे, वे इलाहाबाद में पार्टी की स्पष्ट घोषणा कि हमारे लिये कांग्रेस तथा कम्यूनिस्ट दोनों पार्टियाँ देश में समान असंगत पार्टियां हैं, के बाद भी प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस से समझौते का क्षेत्र व्यापक हुआ है, पार्टी के पिछले फैसले गलत साबित हुए हैं, देश के निर्माण के लिये जनतान्त्रिक पार्टियों (प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी) का समझौता आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी भी समाजवाद ला सकती है। यदि आज की कांग्रेस सन ४८ में ही रही होती तो पार्टी को कांग्रेस से अलग होने की आवश्यकता न होती इत्यादि इत्यादि का नारा पार्टी-मीटिंगों, समाचार पत्रों तथा आम सभाओं में लगाते रहते हैं। पार्टी के कुछ जिम्मदार नेता पार्टी संगठन के तमाम व्यावहारिक कार्यों से अलग होकर पार्टी की घोषित नीति जन-तान्त्रिक समाजवाद तथा वर्ग संघर्ष की प्रणाली की विरुद्ध सर्वोदय

व्यवस्था तथा वर्ग प्रेम का दर्शन खुले आम देने लगे और यहां तक भी ऐलान करने लगे कि मैं गैर पार्टी राजनीतिक व्यवस्था में यकीन करता हूं, मैं पार्टी की मेम्बरी केवल इसलिये कायम रखे हूं जिससे सर्वोदय और पार्टी के बीच एक कड़ो का काम कर सकूँ और दोनों को नजदीक ला दूं।

अब आप स्वयं सोचें कि ऊपर लिखी बातें जब पार्टी के जिम्मेदार माने जाने वाले नेता कहने लगेंगे तो पार्टी का अलग अस्तित्व, शान तथा मर्यादा के साथ चलकर वतमान कांग्रेस राज को कैसे दूर कर सकेगा। इस नीति का नतीजा यह हुआ कि पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति सरकारी कमिटियों में विदेश भो जाने लगे और सारे देश की आम जनता के मन में यह धारणा मजबूत होती चली कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी से मिल जायगी। कुछ नेता लोग आगे आने वाले आम चुनाव में कांग्रेस से सीट का समझौता करके चुनाव लड़ने की बात भी सोचने लगे। इसी बीच में कांग्रेस का अवाडो सम्मेलन हुआ। उसने सोशलिस्टक पैटर्न का नारा बुलन्द किया। कॉंग्रेस के इस नारे के आते ही विभिन्न प्रकार से कॉंग्रेस से समझौता का क्षेत्र व्यापक हुआ की नीति में विश्वास करने वाले लोग अवाडो प्रस्ताव का दिल से स्वागत कर पार्टी की नीति में शीघ्र परिवर्तन करने की माँग करने लगे। बम्बई में कुछ पार्टी सदस्य खुले आम बयान निकाल कर कहने लगे कि पार्टी की नीति पुरानी हो गई इसे बदल कर कांग्रेस से समझौता करना चाहिये। आँध्र में एक ओर सारे सूबे में आम चुनाव हो रहा था साथी मधुलिमये चुनाव दौरा कर रहे थे। वह कहते थे कि कॉंग्रेस के नारे के भ्रम में मत पड़ो, यह नारा धोखा है चुनाव जीतने का षड्यंत्र है, समाजवादी क्रॉंति तो केवल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ही ला सकती है। मधुलिमये के इस बयान का विरोध खुले

आम समाचार पत्रों में कराया गया कि वह मधु का व्यक्तिगत विचार है। मधु ने ऐसे साथियों का विरोध किया और उन्होंने कहा कि इसके पीछे श्री अशोक मेहता का भी हाथ है। बम्बई कारपोरेशन में काँग्रेस के साथ मिलकर काम चलाने के लिये गुप्त मीटिंग भी श्री अशोक मेहता के घर पर हुई। इन तमाम बातों से दुखी होकर मधुलियमे ने बयान दिया कि इन लोगों की मिश्रित आँखें अब केवल पार्टी की ओर ही नहीं है बल्कि काँग्रेस की ओर भी चल पड़ी हैं। इसका खातमा होना चाहिये। इसी के साथ साथ मधु ने बम्बई पार्टी की कौंसिल की मीटिंग में जिसमें अवाडी प्रस्ताव पर विचार हो रहा था और पार्टी की नीति बदलने की माँग की जाने वाली थी मीटिंग के चेयरमैन हरिस की उस व्यवस्था के विरोध में वाक आउट किया जिसमें चेयरमैन ने अनियमित ढंग पर ६ कौंसिलरों को निकाल दिया था। मधु ने वाक आउट किया फिर प्रेस में बयान दिया। अब मधु के ऊपर प्रेस सम्मेलन में बयान देने के कारण बिना उनके ऊपर चार्ज लगाये उनके कहने के बावजूद कि मुझे चार्ज दीजिये कि प्रेस कान्फेन्स में मैंने क्या किया जिस पर आप अनुशासन की कार्यवाही कर रहे हैं, बम्बई पार्टी ने मधु को साल भर के लिये पार्टी की सदस्यता से मुअत्तल कर दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मधु के बार बार के निवेदन पर कि एक ट्राइब्युनल बैठाइये, बम्बई पार्टी के २५० में से १५० सक्रिय सदस्यों की प्राथना पर कि मुअत्तली खतम कीजिये का बिना ख्याल किये हुए पार्टी नियमों को तोड़कर विधान के प्रतिकूल मधुलिमये की मुअत्तलीको मान्यता दे दी।

१—प्रान्तीय कार्यसमिति उ० प्र० की कार्यकारिणी ने अपनी १५, १६ अप्रैल की बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निवेदन किया कि आप पुनः अपने फैसले पर विचार कीजिये हम लोग

मधुलिमये को अपने प्रान्तीय सम्मेलन में बुलाना चाहते हैं। इसमें तनिक भी अनियमितता नहीं। हम निवेदन करने का पूरा हक रखते हैं राष्ट्रीय कार्यसमिति से कह सकते हैं कि आप अपना गलत ढंग बदलिये। पार्टी की छोटी तथा बड़ी शाखाओं का सम्बन्ध तहसीलदार और पटवारी का नहीं है। हमारे निवेदन पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग नहीं बुलाई उल्टे हमसे पूछने लगे कि तुम्हारे ऊपर अनुशासन की कार्यवाही क्यों न की जाय। यह ढंग तानाशाही पार्टी भी नहीं बरत सकती है। महीने के ऊपर समय था देश की सबसे बड़ी सूबे की पार्टी निवेदन करती है मगर राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक नहीं बुलाई जाती।

२—हमने कहा कि आप जनरल कौंसिल की बैठक बुलाइये। हम उसमें पार्टी संगठन नियम अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही पर विचार करेंगे। जनाब फरीदुलहक अन्सारी संयुक्त मन्त्री का जवाब आया कि जनरल कौंसिल की बैठक नहीं बुलायी जा सकती क्योंकि जनरल कौंसिल में अनुशासन की कार्यवाही पर विचार नहीं हो सकता।

३—फिर हमने कहा कि संगठन में अनुशासन आता है तो जनाब फरीद अन्सारी ने कहा कि नहीं संगठन तथा अनुशासन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

४. इसके बाद पार्टी चेयरमैन की राय पहले लिखकर जनाब फरीदुलहक अन्सारी ने राष्ट्रीय कार्य समिति के मेम्बरों की राय मांगने का नायाब गैरजनतान्त्रिक तरीका निकाला कि श्री गोपाल नारायण सक्सेना को क्यों न साल भर के लिए पार्टी सदस्यता से अलग कर दिया जाय उनके बयान की सजा में। यदि राष्ट्रीय

कार्य-समिति के सदस्यों की राय जाननी थी तो पहिले चेयरमैन की राय उनको बताकर प्रभावित क्यों किया गया ?

५. फिर समाजवादी युवक सभा ने साथी मधुलिमये को सम्मेलन के सभापतित्व के लिये आमन्त्रित किया। जनाब फरीदुल-हक अन्सारी साहब का सरक्यूलर निकल गया कि पार्टी का कोई सदस्य इस सम्मेलन में न जाय क्योंकि मधुलिमये मुअत्तल मेम्बर उसके सभापति बनेंगे। इस सरकुलर ने हम सबकी आँखें खोल दीं। एक ओर तो मजदूर संगठनों को तोड़कर कांग्रेस द्वारा संचालित मजदूर संगठनों से समझौता कराया जाता है। पार्लिया-मेन्ट में पार्टी नीति रीति विरोधी कम्यूनिस्ट समर्थक एम० पी० मोरे को लेकर विरोधी पार्टी ही नहीं बनायी जाती है बल्कि उसे उसका मन्त्री बनाया जाता है। तमाम संगठनों को मिलाकर गोवा जन आन्दोलन चलाया जाता है दूसरी ओर मधुलिमये को राजनीतिक अछूत मानकर समाजवादी युवक सभा जो एक स्वतन्त्र संगठन है उसके सम्मेलन में जाने से रोक लगायी जाती है।

अब आप देखेंगे कि

१. राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक बुलाने का मार्ग ठुकराया गया।

२. जनरल कौंसिल की बैठक बुलाने की माँग ठुकरायी गयी।

३. जून में राष्ट्रीय सम्मेलन को बुलाने की माँग की गयी और अपने सूबे में सम्मेलन करने का न्यौता भी दिया गया मगर उसकी भी माँग ठुकरा दी गई और जून में सम्मेलन करने का फैसला बदल दिया गया।

४. मधु की मुअत्तली को मान्यता देने के बाद पार्टी नियमा-

त्तली का भाष्य भी दूसरा होने लगा कि मुअत्तली का सवाल राष्ट्रीय सम्मेलन में भी नहीं उठ सकता। जब इतने बड़े-बड़े व्यापक नीति तथा संगठन के प्रश्न सामने हों तो सम्मेलन को टालना और केवल अनुशासन के नाम पर गलत ढंग से नियमों का मनमाना अर्थ लगाना कहाँ का जनतन्त्र है।

यह प्रश्न मूल प्रश्न है। जो पार्टी देश तथा विदेश में जैसा ढाँचा रखना चाहेगी वैसा ही नियम अपने अन्दर भी चलायेगी। डा० लोहिया से बिना सफाई माँगे ही उनको चेतावनी की सजा देना कहाँ का न्याय है। यह प्रश्न केवल मधुलिमये का नहीं पार्टी की मूल नीति से सम्बन्धित है। इन अन्याय के विरोध में स्वस्थ राजनीतिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए ही प्रान्तीय पार्टी ने मधु के सम्बन्ध में फैसला लिया है कि राष्ट्रीय कार्य समिति का फैसला नियम विरुद्ध है। हमारा फैसला पार्टी नीति रीति तथा नियमानुकूल है। पार्टी की मर्यादा को सुरक्षित रखनेवाला है। हमने थोड़े में सब स्पष्ट किया है, यदि कोई बात साफ न हो तो आप सफाई मांग सकते हैं। यह प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष या नेता विशेष का नहीं है बल्कि सारे संगठन का है। आशा है आप सारी परिस्थिति को जानकर हमारे फैसले का स्वागत करेंगे।

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश का द्वितीय वार्षिक सम्मेलन ११, १२, १३ जून को गाजीपुर में सकुशल समाप्त हो गया।

यह तो आप जानते ही हैं कि यह सम्मेलन प्रान्तीय कार्यसमिति की १२, १३ मार्च की, प्रतापगढ़ की बैठक में निश्चित किया गया था। इसके अनुसार गाजीपुर जिला शाखा ने सारी तैयारियाँ प्रारम्भ कर दीं। इधर प्रान्त भर में पार्टी के चुनाव का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया जिसके अनुसार ५ जून ५५ तक सारा चुनाव समाप्त हो जाना चाहिये था। इस प्रकार जिला या शहर

कौंसलरों का चुनाव भी समाप्त हो गया था जो कि प्रान्तीय सम्मेलन के प्रतिनिधि होते हैं। इसी बीच ६ जून को निगोहां (लखनऊ) सम्मेलन द्वारा चुनी गई कार्यसमिति को राष्ट्रीय कार्यसमिति ने मुअत्तल करके एक एडहाक कमिटी बना दी और गाजीपुर सम्मेलन पर अवैधानिक तरीके पर रोक लगा दी। गाजीपुर सम्मेलन एक वैधानिक सम्मेलन था। वैधानिक सम्मेलन को रोकने का अधिकार विधान के अनुसार राष्ट्रीय कार्यसमिति को कहीं भी नहीं है। यह कार्य करके राष्ट्रीय कार्यसमिति ने अपनी सीमा के बाहर जाकर अवैधानिक रूप का परिचय दिया।

जहाँ तक प्रान्तीय कार्यसमिति की मुअत्तली का प्रश्न है राष्ट्रीय कार्यसमिति के प्रधान मन्त्री ने १६।४।५५ के प्रान्तीय कार्यसमिति के प्रस्ताव पर जिसके द्वारा साथी मधुलिमये के मामले पर राष्ट्रीय कार्यसमिति से पुनर्विचार करने के लिये प्रार्थना की गई थी, पर पुनर्विचार करने के बजाय प्रान्तीय कार्यसमिति से उस प्रस्ताव को पास करने के जुर्म में जवाब तलब किया गया। प्रधान मन्त्री के इस कार्य पर प्रान्तीय कार्यसमिति ने प्रस्ताव पास किया। स्मरणार्थ १६ अप्रैल के प्रस्ताव को प्रो० राजाराम शास्त्री ने लिखा था और उसमें जब कुछ संशोधन आये तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें कुछ भी बदलने को तैयार नहीं हूँ इससे अनुशासन कहीं भी भंग नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि इससे यह भी स्पष्ट है कि अगर राष्ट्रीय कार्यसमिति इस पर पुनर्विचार नहीं करती तो इसका साफ मतलब होगा कि प्रान्तीय कार्यसमिति साथी मधुलिमये को बुलायेगी। आश्चर्य की बात है कि जिसके यह विचार हैं वही काम चलाऊ कमिटी के सभापति बन बैठे।

जब एक सप्ताह के अन्दर ही पुरानी कमिटी अपने आप समाप्त

हो जाती और उसके स्थान पर नई कार्यसमिति चुनी जाती ऐसी अवस्था में राष्ट्रीय कार्यसमिति ने व्यावहारिकता का भी ध्यान न रखकर कार्य किया।

इन सब बातों से स्पष्ट हो गया होगा कि इस प्रान्त में गाजीपुर सम्मेलन में चुनी हुई समिति ही वैधानिक है और सभी साथियों व कमिटियों को इसी के अनुसार काम करना चाहिये।

यहां पर यह भी साफ कर दूँ कि यह सब कदम तभी उठाये गये जबकि राष्ट्रीय जनरल कौंसिल की बैठक बुलाने की मांग ठुकरा दी गई। राष्ट्रीय सम्मेलन जून में करने की मांग नहीं मानी गई जबकि उसको जून में करने के लिये निमन्त्रण दे चुके थे। इसके अलावा और सभी दरवाजे बन्द कर दिये गये। अनुशासन के नाम पर पार्टी के बुनियादी बातों पर पर्दा डालने का तथा उनको टालने की नापाक कोशिश की गई।

आप साथियों को यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जनता की इच्छाओं को साकार बनाने और पार्टी के सदस्यों की इच्छाओं को पूरा करने में यही समिति सफल होगी। हम किसी भी प्रकार पार्टी को छोड़नेवाले नहीं हैं। पार्टी को तोड़ने का काम राष्ट्रीय कार्यसमिति ने एक एडहाक कमिटी बनाकर शुरू कर दिया है ताकि यहाँ के कार्यकर्त्ता भ्रम में पड़ें और शिथिल हो जायँ और उन लोगों का मार्ग सुगम हो जाय जो खुले प्रचार करते हैं कि कोई भी एक पार्टी देश का निर्माण नहीं कर सकती। अगर निर्माण कार्य हो सकता है तो सारी पार्टियों को राष्ट्रीय मोर्चे द्वारा ही या यह प्रचार करने वाले कि कांग्रेस भी समाजवाद ला सकती है। हम यह किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। इस तरह की पार्टी को अनुशासन की आड़ में तोड़ने वालों से आपको सावधान रहना है यही समय की पुकार है।

डा० राममनोहर लोहिया ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा—प्रजा समाजवादी पार्टी का काम ताकत पाने पर समाजवाद की भी स्थापना तथा ताकत पाने के पहले मौजूदा अन्यायों को मिटाने के लिये संघर्ष करना है।

यदि अनुशासनहीनता छिपाने के लिये मत भेद का नारा देने का लांछन लगाया जा सकता है तो यह बात और भी जोर के साथ कही जा सकती है कि मतभेद, कर्म भेद, दृष्टि भेद को छिपाने के लिये ही अनुशासनहीनता का नारा दिया जा रहा है।

आज का प्रश्न नम्बर एक का प्रश्न है आने वाले कल का प्रश्न तो दूसरे नम्बर का है।

पार्टी का कांग्रेस से विलयन मिलीजुली सरकार शर्त के साथ सरकार और रचनात्मक काम में सहयोग के चार विचार प्रकट होते रहते हैं। इसमें आखिरी विचार जो सबसे मासूम लगता है वहा सबसे खतरनाक है। छः मास तक रचना में सहयोग का प्रचार होता हे और वास्तविक रचना में सहयोग होते ही कहना शुरू होता है कि बिना सरकार में सहयोग के रचना में भी सहयोग सम्भव नहीं है।

आन्दोलन और संघर्ष का अन्तर ठीक से समझना होगा। आज देश में कोई भी पार्टी विरोधी दल का काम पूरा नहीं कर रही है। आज की समस्याओं पर लगातार आवाज बुलन्द नहीं हो रही है।

विधान सभाओं को जनता की तकलीफों और आकांक्षाओं का आईना बनना विरोधी पक्ष का काम है। किन्तु देश में आज हो क्या रहा है। आज एक झूठो धारणा बन रही है कि देश तरक्की कर रहा है तब फिर सवाल उठता है कि उसमें अड़ंगा

क्यों लगाया जाय यदि बन पड़े तो मदद की जाय। यह ख्याल बिल्कुल ही गलत है।

१२५ वर्ष के अंग्रेजी राज में हर रोज एक मील रेलवे लाइन बनी, हर चौथे दिन एक स्टेशन बना, हर तीसरे महीने एक सूती मिल खड़ा किया गया तथा हर वर्ष एक शकर की मिल चालू हुई। किन्तु फिर भी भारत की बर्बादी ही उस राज्य में हुई उसी प्रकार आज कुछ लोगों का जो उसमें हिस्सा पा रहे हैं, छोड़कर ३५ करोड़ जनता की जिन्दगी मुसीबत में है। जीवन स्तर गिर रहा है, बेकारी बढ़ रही है। टैक्सों का बोझ भारी होता जा रहा है नागरिक आजादी भी छिनती जा रही है।

बड़ी बातों पर चुप्पी और मामूली छोटी बातों पर आवाज आज की विरोधी पार्टियों का काम है। आज अन्याय का विरोध तथा समाजवाद के निर्माण लायक संगठन खड़ा करना ही कर्तव्य है। ऐसा संगठन ही मौका परस्ती का पुजारी बनने से बच सकेगा। यदि ऐसा न किया जा सका तो खतरा है कि आगे भी राज्य खानदानी गुलामों के हाथों में ही चला जायगा।

साधारण चुनाव के नजदीक होने के डर से मतभेद, कर्मभेद और दृष्टिभेद की सफाई न करना खतरनाक है। चुनाव एक नशा मात्र हो कर रह जायेंगे 'METOO' मैं भी के वसूल से लाभ नहीं होगा। किसी की नकल करने से उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती जनता कांग्रेस से ऊब गई है और हम कांग्रेस के खिलाफ हैं इतने मात्र से चुनाव में जीत की उम्मीद बेकार होगी।

अनुशासन पर बोलते हुये डाक्टर साहब ने आगे कहा कि पार्टी के विभिन्न अंगों के पारस्परिक सम्बन्ध कल भर और पटवारी जैसे न हो कर विधान और नियमों के अनुसार होने चाहिए। आचार संहिता विधान और नियम का स्थान नहीं ले सकती।

आचार संहिता का सम्बन्ध नीति से नहीं आचरण से है। नीति भेद पर बोलने से पार्टी नष्ट नहीं होती बल्कि उसमें सफाई आती है और वह मजबूत होती है।

सिद्धान्त और ठोस अमल के अन्तर को मिटाने से ही पार्टी मजबूत होगी और समाजवाद को कायम करने में सफल हो सकेगी।

———

सम्मेलन का प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का यह सम्मेलन प्रदेश के समाजवादियों को बधाई देता है कि उन्होंने प्रजातन्त्र और समाजवाद का खात्मा करने वाली तानाशाही की परवाह न कर अपने पूर्व सकल्प को पूरा किया। दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तानाशाही ने तो विधान और अनुशासन के सभी नियमों को तोड़ा, मुअतल सदस्यों को न सिर्फ प्रतिनिधित्व के अधिकारों से वंचित किया बल्कि उनके बोली के अधिकारों को छीनना चाहा, मुअत्तिली ने इन्तजामी नियमों को गैर कानूनी और अनैतिक ढंग पर खींच कर नीति विचारों और विवाद पर रोक लगाना चाहा, बिना नियम और अधिकार के न सिर्फ एक प्रदेश की कार्यकारिणी को भंग करना चाहा बल्कि उसके प्रतिनिधि सम्मेलन को तोड़ने की अनहोनी औरमारक कोशिश की। प्रदेश की कार्यकारिणी बहुत और मर्यादा से अधिक झुकी लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अपने प्रयत्नों से साबित किया कि उसे इज्जत शक्ति या ऐसी ही किसी रीति नीति की बेहोश तलाश थी। ऐसे प्रयत्नों के सामने घुटने टेकने प्रजातन्त्र और समाजवाद के नन्हें बच्चे का गला घोंटने में सहायता करना होता वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के समाजवादियों ने इनका मुकाबिला कर दलों के आन्तरिक प्रजातन्त्र की रक्षा कर देश के प्रजातन्त्र की नींव को बढ़ाया और गहरा किया।

सम्मेलन की राय में यदि अनुशासन हीनता को छिपाने के लिये मतभेदों की आड़ ली जा सकती है तो उससे भी अधिक और जो आजकल हो रहा है मतभेदों को छिपाने और निपटाने के लिये अनुशासनहीनता की पुकार मचाई जा सकती है। समाजवाद के दल में निस्संदेह बहुत अर्से से मतभेद, नीतिभेद, कर्मभेद और दृष्टिभेद उचित सीमाओं के बाहर होते जा रहे थे और विचारों और कामों के द्वारा उनकी सफाई करते रहना आवश्यक भी है लेकिन उन्हें एक तरफ तो इनकार करके और दूसरी तरफ अनुशासन की कार्रवाई करके सुलझाना न सिर्फ असत्य बल्कि घातक है। किसी भी संगठन में अनुशासन उद्देश्य की पूर्ति और नियमों के आधार पर होना चाहिये। राष्ट्रीय कार्यकारिणी न विधान और नियमों की अवहेलना करके एक लौकिक किन्तु भ्रान्त धारणा का सहारा लिया कि मातहत कमेटियों और व्यक्तियों को ऊपरी व्यक्तियों और कमिटियों का हुक्म मानना चाहिये। दरअसल प्रजातन्त्री संगठन और अनुशासन कभी भी पटवारी कमिटियों या व्यक्तियों के आधार पर हो नहीं सकता और सभी व्यक्ति या कमिटियों, क्या मातहत और क्या ऊपर वालों को नियमों की सीमाओं के अन्दर रहना चाहिये। उत्तर प्रदेश की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी सारी भारतीय जनता की बधाई का पात्र है। उसने गहरी चोट खाकर भी संगठन और अनुशासन के इस मारक पटवारी अमल पर कुठाराघात किया।

सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार का अनुशासन किसी भी संगठन के लिये देह का पंजर है। किसी भी दल के सदस्यों को ओहदों आदि के आपसी झगड़ों जुर्म के पारस्परिक आरोपों को खुल्लम खुल्ला न करना चाहिये और न उन्हें एक दूसरे के खिलाफ दल के बाहर चुनाव लड़ना चाहिये। ऐसा करने वालों को अनुशासित करना चाहिये। लेकिन मत, नीति और कर्मभेद

सम्बन्धी शब्दों पर चाहे वे कितनी ही कठोर क्यों न हों व्यवहारिक नाराजी के अलावा और कानूनी अथवा अनुशासन की कार्रवाई होने लगे तो पक्षपात होता है, एक तरफ की कठोरता जरूरत से ज्यादा दीखती है और दूसरी आंखों से ओझल होती है। प्रजातन्त्र तो खतम होता ही है साथ साथ दल का टूटना भी अनिवार्य हो जाता है। सकारात्मक अनुशासन की और भी आवश्यकता है। और यह व्यक्तित्ववाद या मौकेबाजी के आधार पर नहीं बल्कि सिद्धान्तों के आधार पर ही रचा जा सकता है। वे बेपेंदे के लोग क्या अनुशासन रचायेंगे जो आज तो कार्यकारिणी के प्रस्ताव के साथ साथ हैं और कल कार्रवाई होने पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तानाशाही कमिटी के सदस्य हो जाते हैं। विचारों और व्यवहार की शीलता के अलावा यह भी जरूरी है कि मेम्बरी और कमिटियों सम्बन्धी वैधानिक नियमों का कानूनी पालन किया जाय और और पार्टी के नाम पर चुनाव इत्यादि वहीं लड़े जाँय जहाँ कि कमिटियों और उम्मीदवार के विधान और नियमों के अनुसार हों। समाजवादियों को यह भी शीघ्रातिशीघ्र समझ लेना चाहिये कि ऊपर से नीचे की तरफ पैसों की प्रतीक्षा रहने पर अनुशासन कभी रचा ही नहीं जा सकता।

उत्तर प्रदेश प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का यह सम्मेलन संगठन के इन सिद्धांतों को देश की वर्तमान स्थिति में और भी जरूरी समझता है कि एक तरफ बेकारी बढ़ती चली जा रही है, बेदखलियाँ हो रही हैं, किसानी उपजों की कीमतें घट रही हैं, जहाँ कि टैक्स बढ़ रहे हैं, कारखानों के माल की कीमतें स्थिर हैं अथवा बढ़ रही है और बावजूद ऊपरी नकली या अति सीमित पुनर्निर्माण के जनता का दुख बढ़ता ही जा रहा है, पुलिस जुल्म से जनता त्रस्त है। दूसरी तरफ साधारण चुनाव का समय नजदीक आ रहा है किन्तु जहाँ

सरकारी पार्टी कम से कम देखने में सबल हो रही है विरोधी पार्टियाँ कमजोर होती दीख रही हैं बहुत दुख और घटते विरोध के सह अस्तित्व का बेला में प्रजा सोशालिस्ट पार्टी का दिशा भ्रम बहुत ही हानिकारक है। कांग्रेस पार्टी के साथ विलयन, मिली जुली सरकार, शर्तों पर मिली जुली सरकार अथवा स्थायी सहयोग की बातें और सम्बन्धित घटनायें इतनी बार बार लेकिन अलग अलग लोगों की ओर से होती रहती हैं किन्तु उनकी सफाई देना गैरजरूरी हो गया है। इन सब बातों और घटनाओं का कोई आखिरी परिणाम चाहे निकले या नहीं लेकिन वर्तमान में जो यह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को हर तरह से पंगु बना देती है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का कोई सदस्य या गिरोह भविष्य में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलेगा या नहीं ऐसी थोथी बहस को छोड़कर असली बहस को ढक दिया जाता है कि यह दल वर्तमान में किस हद तक और किन तत्वों द्वारा पंगु समाजवाद या सक्रिय समाजवाद का प्रेरक है। कांग्रेस शक्ति और समाजवादी बुद्धि को देश निर्माण के लिये जोड़ने की बेकार कोशिश से पंगु समाजवाद को और भी बल मिलता है तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को जनता की पार्टी बनाने का काम रोककर उसे २००-३०० सफल नेताओं अथवा विधायकों के निर्माण का साधन मात्र बनाने की कोशिश की है। इन गलत धारणाओं के साथ साथ साधारण चुनाव के नजदीक आने के कारण सौदे बाजी का नशा बढ़ना स्वाभाविक ही है। जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की ऊपरी एकता और अन्दरूनी खोखलापन कायम रखने में मदद देता है और जिससे जुए की तरह चुनाव जीतना दिखाई तो देता है किन्तु जीत होती नहीं। हिन्दुस्तान की राजनीति एक महान दलदल है जिसमें सिद्धांतों, व तदरूप कर्म और संगठन के खूँटे गाड़े बगैर न तत्कालिक जीत ही सम्भव है और न समाजवाद का निर्माण

ही। यह जरूरी है कि बढ़ते हुये दुख का डटकर और लगातार विरोध किया जाय और, काम अथवा भत्ता, मूल्य संतुलन जिसके अनुसार घटते दामों के समय बढ़ते टैक्स अनुचित हैं भूमि संबंधी अन्यायों जैसे बेदखली इत्यादि को रोकने की नीतियों के आधार पर सामूहिक संगठित आन्दोलन हो। तथा जरूरत पड़ने पर अन्यायी कानूनों और इन्तजामों को तोड़ा जाय।

सारे देश के प्रजा समाजवादी पार्टी के सदस्यों और शाखाओं का जो पंगु समाजवाद को हराकर सक्रिय समाजवाद को जिताना जाहते हैं कर्तव्य बढ़ गया है कि वे अपनी पार्टी को उपयुक्त औजार बनावें रचना आन्दोलन तथा संघर्ष, संगठन तथा राजनैतिक शिक्षा के पारस्परिक पूरक कामों के आधार पर एक तन्दुरुस्त आवोहवा पैदा करें जिससे सक्रिय समाजवाद को बल मिले। उत्तर प्रदेश प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का यह सम्मेलन देश के सभी समाजवादियों को चेतावनी देता है कि वे शीघ्रातिशीघ्र :

१. सदस्यता और शाखाओं के वैधानिक नियमों का पालन करते हुये अपने दल का संगठन बनावें।

२. रचनात्मक काम करें।

३. अन्यायों के विरोध में संगठित आन्दोलन तथा जरूरत पड़ने पर संघर्ष करें।

४. सविनय अवज्ञा की नींव पर साधारण बहादुरी वाला नया व्यक्ति बनाने में मदद करें।

५. किसान पंचायत मजदूर सभा, समाजवादी युवक सभा जैसे संगठन बनावें। वर्ग संघर्ष करें और उसका तथा समाजवादी पार्टी का वैज्ञानिक नाता फिर जुड़वाने की कोशिश करें।

६. साधारण राजनीतिक प्रचार को उद्देश्य मूलक बनाने के साथ साथ कार्यकर्ताओं के लिये शिक्षण शिविर चलावें।

७. एक तरफ विधायक उमीदवारों का नियमों और सिद्धाँतों के आधार पर निर्माण करें और दूसरी तरफ उनकी क्षेत्र कमिटियों के सशक्त कमिटियों का।

उत्तर प्रदेश प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का यह सम्मेलन प्रदेश की सभी समाजवादियों से अनुरोध करता है कि वे तानाशाही द्वारा निर्मित एडहाक कमिटी को न मानते हुये उससे सहयोग न करें। पार्टी में फूट डालने का और दूसरी पार्टी बनानेका काम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने शुरू कर दिया है और उनको नाकामयाब बनाने का कर्तव्य एक हर समाजवादी को है। यह सम्मेलन देश के सभी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों और शाखाओं, न सिर्फ प्रदेश तथा जिला बल्कि क्षेत्र कमिटियों से भी अनुरोध करता है कि वे इस प्रस्ताव पर बहस करें, अपनी राय बनावें और प्रस्ताव पास करें। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विरोध करें और उसे हटाने की माँग करें।

गाजीपुर १२ जून १९५५।

प्र० डा० राम मनोहर लोहिया,
स० राजनारायण एम. एल. ए.

प्रस्ताव पर बहस

परमहंस त्रिपाठी (देवरिया)

देवरिया जिला में किस प्रकार की नेतागिरी चलती है उसके कुछ नमूने देखिए। उन लोगों की हमेशा मनोवृत्ति रहती है कि बातों को छिपाये रखें। पार्टी की बातें पूरी नहीं बताते। वह दूसरे कार्यकर्त्ताओं को नहीं चाहते कि पार्टी के बारे में कुछ सोचें। श्री गेन्दासिंह ने ६ जून १६५५ को जिला मंत्री पद के लिए अपना नाम स्वयं ४ बार पेश किया किन्तु वे नहीं चुने गए, क्योंकि वे सक्रिय सदस्य नहीं थे। यह प्रस्तव जो आपके सामने है इसे दृढ़ता के साथ मनवाना चाहिए। और देवरिया का बहुमत आपके साथ है।

प्रो० बासु देव सिंह (प्रतापगढ़)

मैं इस प्रस्ताव का प्रेम और श्रद्धा से समर्थन करता हूँ। राष्ट्रीय कार्य कारिणी इस समय अवास्तविक हो गई है। आज वह स्वस्थ और लड़ाकू नीति चाहती है या कांग्रेस से मिलना चाहती है? हमारी नीति स्पष्ट होनी चाहिए। हमारे काम में स्पष्टता होनी चाहिए। कथनी से तारीफ़ और करनी से विरोध, इस भावना को छोड़ना पड़ेगा। हमें सिद्धान्तों के पीछे चलने की क्षमता होनी

चाहिए। मैं पार्टी में इसलिए आया हूँ कि इसमें एक नेता ऐसा है जो निःस्पृह और सिद्धान्त के पीछे चलने वाला है।

श्री हरि किशोर (उन्नाव)

आज सभी बातें खुल्लम-खुल्ला हमारे सामने आ गई हैं। प्रस्ताव में सभी बातें सफाई से आ गई हैं। पार्टी के अन्दर पार्टी को कमजोर करने वाले व्यक्तियों और प्रवृत्तियों का विरोध करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि प्रस्ताव में "तानाशाही" शब्द के स्थान पर "अवैधानिक" या "अधिनायक" होना चाहिए।

ओम प्रकाश दीपक (इलाहाबाद)

इस समय पार्टी में यह कोशिश की जा रही है कि पार्टी निष्क्रिय होती जाय। कुछ लोग प्रजा सो० पार्टी को समाजवाद का साधन नहीं बनने देना चाहते। ऐसे लोगों के लिए मोह भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग एकता की बात करते हैं। आखिर किस चीज की एकता। जहां बुनियाद ही बिगड़ गई है वहां यह सवाल ही कहां पैदा होता है।

डा० केदार नाथ (आजम गढ़)

मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यहां केवल सुधारवाद की बात हो रही है। पार्टी में सुधार नामुमकिन है फिर भी हम कोशिश करेंगे। हमारी नीति साफ है। हम प्रचारवाद भी नहीं चाहते किन्तु लोहिया जी प्रस्ताव के अन्तिम पैराग्राफ का पुनः स्पष्टीकरण करें।

: कृष्णनारायण (बनारस)

हमें सोशलिस्ट तहरीक में एक नया मोड़ देना है। विलयन

के समय कहा गया था कि कार्यक्रम के अनुसार समाजवादी आन्दोलन को चलाना होगा—दर्शन के संबंध में सबसे राय रखने की स्वतंत्रता,होगी। आज प्रचार हो रहा है कि नीति भेद नहीं है—अनुशासन हीनता है। हम आचार्य नरेन्द्रदेव जी की इज्जत करते हैं किन्तु वे इस प्रकार की बात करते हैं जिसमें बहुत से ईमानदार सोशलिस्टों पर शक किया है। हमने फैसला ईमानदारों की सिकायत के लिए किया था। जिन लोगों ने वर्ग संघर्ष के आधार पर समाज रचना की बात की थी आज वे उसकी बात तक नहीं करते।

रामआधार गिरि (बनारस)

ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

समशी मीनाई (गोण्डा)

मैं सदर साहब से उस खत को पढ़ने की इजाजत चाहूँगा जिसे मैंने जनाब फ़रीद अनसारी को लिखा था। सभापति की आज्ञा पाने पर उस खत को पढ़ा। इसके बाद उन्होंने कहा कि ६ मई को दिल्ली में पश्चिमी जिलों के कार्यकर्त्ताओं की बैठक बुलाई गई थी उसमें मुझे शामिल होने से रोका गया—जब कि मैं प्रान्तीय कार्यसमिति का सदस्य था। लेकिन प्रान्तीय मंत्री की इजाज़त लेकर उसमें शामिल हुआ। इसी से आपको सभी बातों का अन्दाजा लगा लेना चाहिए। हम यह भी साफ कर देना चाहते हैं कि व्यक्तियों के पीछे चलना छोड़िये—हम यहाँ लोहिया भक्ति में नहीं आए हैं। मजबूती से जड़ को पकड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए।

काशीनाथ मिश्र (बलिया)

बीच बीच में चुनाव, समझौते आदि की बातों से पार्टी की

शक्ति कमजोर होती है। भूदान और सर्वोदय, वर्ग संघर्ष और वर्ग समन्वय ये अलग चीजें हैं। पंचमढ़ी तक नीति के संबंध में जहाँ लोहिया जी अल्प मत में थे उसके बाद ही बहुमत हो गए। लेकिन बहुमत को निष्क्रिय बनाने की कोशिश आज भी जारी है। इसका हमें डटकर मुक़ाबिला करना है।

मोहर राम (देवरिया)

हम जब देवरिया में काम करते हैं तो लोग पूछते हैं कि तुम क्यों ऐसा करते हो। तुम मंत्री होगे या एम. एल. ए.। मैंने कहा कि यह सब तो हम नहीं होंगे लेकिन हमारा डुग्गी पीटना कौन बन्द करेगा। लोहिया जी जब देवरिया गए थे तो उन्होंने कहा था कि जब फावड़ा कमजोर हो जाय तो उसे बदल देना चाहिए। मैं अनपढ़ हूं लेकिन किसान में विचार तो प्रगट कर ही सकता हूँ।

जब सबकी प्रार्थना अस्वीकार कर समुद्रदेव ने सेतु बांधने के सारे प्रयत्नों को विफल कर दिया तब लक्ष्मण ने तीर खींचा और उसके बाद ही समुद्रदेव ने सेतु बांधने में सहयोग दिया। आज सारे प्रयत्न विफल होने पर डा० लोहिया ने भी तीर ताना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोहिया की इसमें जीत होगी।

जब मैं स्टेशन पर आ रहा था तो कुछ लोगों ने पर्चे दिए और कहा कि इस सम्मेलन में मत जाओ। उनसे मैंने साफ़ साफ़ कह दिया कि तुम भी अपनी दूकान खोलकर बैठ जाओ—जिनको तुम्हारी दूकान का माल पसंद होगा खरीदेगा। मुझे तो लोहिया की दूकान का माल पसंद है और मैं उसी की दूकान का सामान ख़रीदूँगा।

च० सिं० करुणेश—

बागी साथियो ! आज हम सब बागी कहे जा रहे हैं। प्र. सो.

पार्टी नये समाज तथा नये मानव की रचना के लिये है। आप का यही कसूर है कि आप इन्सानियत के लिये लड़ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि:—

अगर इन्सानियत का नाम लेना ही
बगावत है।
अगर हैवानियत से होड़ लेना ही,
बगावत है।
तो मैं सौ बार बागी हूँ,
बगावत काम है मेरा।

मेरा विश्वास है कि इस बगावत से पार्टी में जान आई है। राष्ट्रीय कार्यसमिति के निकम्मेपन के कारण पार्टी मर रही थी। उ० प्र० के इसे नये मोड़ से पार्टी जिन्दा हुई। आप सब मुबारकवाद के हकदार हैं।

मेरे प्रस्ताव के द्वारा ही प्रादेशिक कार्य समिति ने साथी मधु को गाजीपुर बुलाया था। इस तरह मेरी ज्यादा जिम्मेदारी है। साथी अशोक मेहता कांग्रेस से दिल से बात करें, साथी जयप्रकाश नारायण यह कहें कि 'अगर अवाड़ी प्रस्ताव ४८ ई० से पहले आ गया होता तो मैं पार्टी को कांग्रेस से अलग न होने देता' तो वे निर्दोष हैं और उ० प्र० की पार्टी दरखास्त करे कि साथी मधु के मामले पर फिर से विचार कर लिया जाय तो हम गुनहगार हो जाते हैं। कितना अंधेर है।

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।

मगर साथियो, बाहरी अन्यायों से वही लड़ सकता है, जो भीतरी जुल्मों के खिलाफ बगावत करता है।

गाजीपुर सम्मेलन के इस प्रस्ताव से पार्टी का लड़ाकू स्वरूप देश के सामने आवेगा। यही जनता के सपनों को साकार करने वाली नयी पार्टी होगी। प्र. सो. पा. हमारी है हमारी रहेगी।

व्यक्तियों के नहीं, उनके विचारों के उपासक हमें बनना है। आज डा० लोहिया प्रकाशस्तम्भ का काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। यदि वे भी धोखा देंगे, तो हमें उनसे भी नाता तोड़ने को तैयार रहना चाहिये। तभी समाजवाद आ सकेगा।

इस प्रस्ताव के संदेश को हम जन-जन और मन-मन तक पहुँचाने जुट पड़ें, यही इस ऐतिहासिक सम्मेलन की सार्थकता होगी।

इसके अलावा साथी मधुकर दिघे विजय कुमार, विश्वनाथ-सिंह सूबेदार गहमरी, आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए लेकिन इनके भाषण के नोट नहीं लिए जा सके थे इसलिए यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं।

डा० राममनोहर लोहिया ने प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि मुझे बहस के किसी बात का जवाब नहीं देना है। एक चीज़ याद रखने की है कि प्र. सो. पा. में बहुत से रत्न छिपे हैं। अभी तक जो भी बोले उत्साह और प्रेरणा देकर गए। मैं सोचता था यहाँ की बहस कुछ रंगीन होगी लेकिन ऐसा नहीं रहा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अब तक के प्रान्तीय या राष्ट्रीय सम्मेलनों से यहाँ की बहस का स्तर बहुत ऊँचा रहा। कुछ सदस्यों ने एक आध शब्द पर आपत्ति की है। शब्दों का एक महत्व होता है। अभी अपने देश की भाषा नहीं बन पाई है। एक ओर अरबी और फ़ारसी का माध्यम है तो दूसरी ओर संस्कृत का माध्यम है। बोलचाल की भाषा के माध्यम के लेहाज से ये शब्द उपयुक्त हैं। तानाशाही और अधिनायकत्व में कोई फ़र्क़ नहीं है। हमारा जो

प्रस्ताव है वह कठोरता और तीखापन के हिसाब से नहीं लिखा गया है। अनपढ़ और पढ़े लिखे का आपसी रिश्ता इससे कायम कर सकेंगे और आगे चलकर हम अपनी जुबान ठीक कर सकेंगे।

डा० केदारनाथ की बात पर मैं कुछ बताऊँगा। उनकी बुनियादी बात इसमें है कि राष्ट्रीय कार्यसमिति को हटाने की माँग किससे की जाती है। (१) या तो सभी सदस्यों के सामने रखा जाय, या (२) प्रतिनिधि सम्मेलन से माँग करे। अर्जुन सिंह भदोरिया जी की बात कि 'हटाने' की जगह पर शब्द 'तब्दीली' रखा जाय। ये दोनों शब्द एक ही हैं। दोनों में से किसी का ज्यादा या कम महत्व नहीं है।

किसी कमिटी या सदस्य को दिमाग़ में ताला लगाकर नहीं सोचना चाहिए। यह पार्टी तो इतनी अनुशासन विहीन हो गई है कि इसको रहने का क़ानूनी हक़ नहीं रह गया है। जिले में कार्यकर्त्ताओं की मीटिंग का उतना महत्व नहीं जितना कौंसिल का या कमिटी का होता है। गांव या हल्क़ा, क्षेत्र तथा जिले में नाता रिश्ता रखना हो तो अपने सोचने के ढंग में परिवर्तन करना होगा। विधान में लिखा है कि हल्का कमिटी की मीटिंग साल भर में ६ होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। इनकी मीटिंगें होनी चाहिए। हर मसले पर इनकी राय की कीमत होनी चाहिए। नागपूर की ही बात लीजिए। हम वहाँ गए—कुछ निजी मोह था। लेकिन फिर भी इस पर हल्का कमिटियों को भी राय देनी चाहिए। ग़ुस्से पर कब्जा करना सीखो। नीचे की कमिटियाँ भी प्रस्ताव पास करें। हो सकता है पहिले ग़लत प्रस्ताव पास करें लेकिन बाद में वही सही प्रस्ताव पास करने लगेंगी। जो प्रस्ताव आपके सामने है इस पर नीचे की कमिटियों से बहस कराइए, चाहे यह पास हो या न हो। जहाँ कहीं पास हो सके पास कराओ।

उत्तर प्रदेश की पार्टी सबसे ग़रीब पार्टी है। ५१ जिलों का काम १८०००) साल में नहीं हो सकता। अगर काम नहीं चला सकते तो आलोचना क्या करोगे। आख़िर यह पैसा कहाँ से आएगा ऊपर से पैसे का मोह छोड़ना चाहिए। अकेले कानपुर से १२०००) साल भर में मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलता। स्वार्थ होता है कि अपने जिले के काम के लिए तो रुपया इकट्ठा करें लेकिन यह सोचते कि सूबे का काम कैसे चलेगा। अगर सूबे का काम ढीला हुआ तो आप ख़ुद ढीले पड़ जाँयगे। ग़ाज़ीपुर सम्मेलन में अधिकांश लोग पैसे की कमी के कारण नहीं आ सके। हमारे सूबे में यह अच्छी आदत है कि लोग बिना टिकट सफ़र नहीं करते। सम्मेलनों में जाने के लिए भी स्थानीय पार्टियों को पैसा देना चाहिए। हिन्द किसान पंचायत का काम आगे बढ़ सकता है लेकिन पैसा नहीं है। वर्ग संगठनों को मज़बूत बनाना है।

सरदारी वाले मामले में मुझे झिझक रही है। मैं कभी भी सरदारी पसंद नहीं करता। सरदारी वाली बात कभी भी जोड़नी नहीं चाहिये। मेरे बदलने का सवाल नहीं रह गया है। अगर अगले ६-७ महीने में पार्टी ठीक नहीं कर सके और नई पार्टी भी नहीं बना सके तो आखिर मैं भी आदमी हूं और अपने सम्बन्ध में फैसला कर सकता हूँ। पारस्परिक आपसी खुशी का रिश्ता होना चाहिये।

यू० पी० की पार्टी की तबियत हरी रहनी चाहिये। सारे हिन्दुस्तान की पार्टियाँ आपके साथ हैं। अगर मेरे जाने पर कोई पार्टी हिम्मत दिखाती है तो उसे मैं हार मानता हूँ जीत नहीं। यह शरम की बात है।

दूसरी पार्टी बनाने का सवाल जिन्हें सुनने में बुरा लगता है उनको ही सबसे अच्छा लगता है। जब पार्टी को सुधारने में

लगोगे तो इसके कई नतीजे निगलेंगे। किसी के ऊपर व्यक्तिगत बातों पर आक्षेप लगाना या सुनना बुरा है मैं नेहरू के व्यक्तिगत बातों पर आक्षेप नहीं सुनना पसंद करता। आपको एक बात और बता दूँ कि आप लोग अपने मुख्य काम को कभी न भूलें। मैं अपने साथियों पर कभी वार नहीं करता और उसे पसंद भी नहीं करता। जब वार करता हूँ तो दुश्मन पर।

अभी सन्मार्ग अखबार का एक पर्चा बंटा है। इस प्रकार की हरकतों से घृणा होती है। एक बहस को एक हद पर ही ले जाना चाहिये। पार्टी में यह बहस ढाई वर्ष से चल रही है। इस घिन्न को अब और नहीं बढ़ने देना चाहिये।

नई पार्टी बनाना आसान नहीं है। लेकिन यदि हम इस घिन्न को भी नहीं खत्म कर सके और नई पार्टी भी नहीं बना सके तो हिन्दुस्तान की जनता एक नई पार्टी का निर्माण करेगी। अपना दिमाग साफ रखना चाहिये। मैं कभी भी गोल बात करने का आदी नहीं हूँ। आखिर मैं अकेले नहीं हूँ इतने प्रतिनिधि भी हैं।

अन्त में मैं आप लोगों की सूचना के लिये बता देना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि मैं हठी हूँ और किसी को बुलाने पर भी उससे बात नहीं करता। मुझे राष्ट्रीय कार्यसिमिति की ४ ५ जून को होने वाली बैठक का निमंत्रण तार द्वारा मिला। कार्यसिमिति में न जाने के विषय में मैंने पार्टी के चेयरमैन को लिखकर भेज दिया था। परन्तु मुझे इसके अलावा कोई भी खत आचार्य नरेन्द्र जी का नहीं मिला कि दिल्ली आकर उनसे राष्ट्रीय कार्यसिमिति की बैठक के पहिले बातचीत करूं। साधारणतया हर एक व्यक्ति के बुलाने पर मैं चला ही आऊं, यह आवश्यक नहीं है, परन्तु आप जानते ही हो कि मेरा और नरेन्द्र देव जी का ऐसा सम्बन्ध है जिसमें कि मैं उनके निनंत्रण को अस्वीकार न करता।

कानपुर हड़ताल

कानपुर सूती उद्योग के लगभग ४५ हजार मजदूरों की आम हड़ताल को ४३ दिन हो चुके लेकिन सरकार अभी अपनी हठवादिता पर अडिग है।

अभिनवीकरण के मसले को ट्राइब्युनल के सामने सिपुर्द करने की साधारण सी माँग को अखिल देशीय समर्थन के बाद भी लगातार ठुकराया जाना मिल मालिकों और सरकार के नापाक गठबन्धन की नंगी तसवीर है। हड़ताल को कुचलने के लिये एक हजार से अधिक मजदूर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, पुलिस आतंक, मारपीट और झूठे मुकदमों तक ही नौकरशाही के हाथ नहीं रुके बल्कि मजदूर महिलाओं के जुलूस पर भी गर्म पानी की बौछार करके लाठी चार्ज किया गया।

यह सम्मेलन सरकार की इस बर्बरतापूर्ण कार्यवाहियों की कड़े शब्दों में निन्दा करता है और सरकार को चेतावनी देता है कि वह पूँजीपतियों के हित के लिये हजारों मजदूरों को तबाह करने का हठ त्यागकर रेशनलाइजेशन के प्रश्न को ट्राइब्युनल के सिपुर्द करने की मांग को स्वीकार कर जनमत के प्रति आदर व्यक्त करे।

सम्मेलन हड़तालियों के साथ राजनीतिक वंदियों का सा व्यवहार न करने के लिये भी सरकार की भर्त्सना करता है और

आशा करता है कि वह प्रतिशोध की दुर्भावनावश जितने नीचे स्तर पर उतर आये हैं उससे कुछ ऊपर उठेगी। तथा सारी दुनिया में राजनैतिक वंदियों के साथ विशेष व्यवहार किये जाने की मान्यता का निरंतर उल्लंघन करने की दुर्नीति का परित्याग करेगी। सम्मेलन प्रदेश की पार्टी की शाखाओं एवं कार्यकर्ताओं से कानपुर हड़ताल की गम्भीरता अनुभव करने और पूरी शक्ति से समर्थन तथा सहयोग देने का आदेश देता है। सम्मेलन का विश्वास है कि कानपुर का संगठित हड़ताली मजदूर और जनमत अवश्य विजयी होगा।

यह सम्मेलन कानपुर के बहादुर मजदूरों को सरकार, मिल मालिकों और आई० एन० टी० यू० सी० की त्रिकोणात्मक शक्ति से मोर्चा लेने के लिए बधाई देता है और उन परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रदर्शित करता है जिनके कारण भरण पोषण कर्ता जेल की चहारदीवारों में बंद हैं।

इस सम्मेलन का दृढ़मत है कि कानपुर के मजदूर भाई जो लड़ाई चलाते हुए कुर्बानियाँ दे रहे हैं वह एक ऐसे इतिहास का निर्माण कर रहे हैं जिसके प्रकाश में देश का गरीब मजदूर तेजी से कदम बढ़ाने की प्रेरणा प्राप्त करता रहेगा।

प्रस्तावक—रेवाशंकर त्रिवेदी
(कानपुर)
समर्थक—मधुकर दिघे
(गोरखपुर)

प्रतिनिधियों की संख्या तथा प्रमुख साथियों की सूची

१—आजमगढ़	२५	१—श्री विश्रामराय एम. एल. ए. मंत्री
		२—,, पद्माकर लाल
		३—डा० केदारनाथ
		४—,, माताभीख जी
		५—,, त्रिलोकीनाथ अग्रवाल
२—अलमोड़ा	१	द्वारिका प्रसाद अग्रवाल, मंत्री
३—इलाहाबाद	[illegible]३	धर्मवीर गोस्वामी
		रजनीकान्त वर्मा
		ओमप्रकाश दीपक
४—बलिया	८	१—रामचन्द्र प्रसाद वकील, सं. मंत्री
		२—काशीनाथ मिश्र
		३—रामनगीना तिवारी
५—बाराबंकी	२५	१—श्री अवधशरण वर्मा
		२—श्री रामसेवक यादव
		३—श्री गिरिजा प्रसाद शुक्ल, मंत्री
६—बस्ती	२	शिवदोहल मिश्र
		अध्यात्म त्रिपाठी
७—बनारस जिला	६२	१—श्री राजनारायण M. L. A.
		२—,, प्रभुनारायण M. L. C.
		३—,, रामअधार गिरि

		४—श्री रामाधार सिंह
८—बनारस शहर	५	सुनील मुखोपाध्याय
९ देवरिया	४०	१—श्री परमहंस त्रिपाठी
		२—,, चन्द्रबली सिंह
		३—,, मोहर राम
		४—,, कृष्ण राम
		५—,, उमाशंकर त्रिपाठी, संयुक्त मंत्री
१०—इटावा	१	अर्जुनसिंह भदौरिया
११—फैजाबाद	४	रामनारायण त्रिपाठी
		सिब्ते मुहम्मद, सं. मंत्री
		डा० राममनोहर लोहिया
१२—गोण्डा	२	१—शमसी मी नाई
		२—नरेन्द्र श्रीवास्तव
१३—गोरखपुर	१५	१—मधुकर दिघे
		२—अश्विनी कुमार शुक्ला
		३—श्रीमती दुलारी देवी
१४—गाजीपुर	६२	१—दलशृंगार दुबे
		२—राजवंशलाल, मंत्री
		३—विश्वनाथ सिंह सूबेदार गहमरी
		४—स्वामी भगवान
		५—जमुनासिंह एम. एल. ए.
		६—सूबेदार सिंह
		७—त्रिवेणीराय
		८—शिवमूरत सिंह
		९—श्रीमती कलावती
१५—जौनपुर	२०	१—श्री रामनरेश सिंह मढ़ी

		२—,, हरिप्रसाद सिंह
		३—,, राजमणि मिश्र
		४—,, रामनिरंजन शुक्ल
१६—कानपुर जिला	२०	१—श्री चन्द्रशेखर तिवारी, मंत्री
		२—,, बलवान सिंह
		३—,, रामस्वरूप वर्मा
		४—,, जगदीश अवस्थी
१७—कानपुर शहर	२०	१—रेवाशंकर त्रिवेदी, मंत्री
		२—प्रभुदयाल टंडन
		३—लोकनाथ जोशी
		४—देवीदत्त अग्निहोत्री
		५—बमशंकर शुक्ल
१८—लखनऊ जिला	१	१—रामसागर मिश्र, सं. मंत्री
१९—लखनऊ शहर	४	१—चं. सिं. करुणेश
		२—रामचन्द्र शुक्ल
		३—गोपाल नारायण सक्सेना
२०—मिर्जापुर	१२	१—नृसिंह नाथ तिवारी, सं. मंत्री
		२—शिवदास तिवारी
		३—ललन सिंह, सं. मंत्री
२१—मुजफ्फरनगर	१	बृजमोहन सिंगल
२२—प्रतापगढ़	५०	१—प्रो० वासुदेव सिंह, मंत्री
		२—नन्दराम गुप्ता
		३—कुंवर तेजभान सिंह
		४—कृष्ण शरण सिंह
		५—रामस्वरूप कंटक

२३—उन्नाव	४	१—शिवप्यारे शुक्ल, मंत्री
		२—चौ. खजान सिंह
		३—हरिकिशोर वाजपेयी

प्रान्तीय कार्यसमिति की सूची

१—श्री गोपालनारायण सक्सेना			अध्यक्ष
२—श्री रामचन्द्र शुक्ल			प्रादेशिक मंत्री
३—श्री चन्द्रिका सिंह करुणेश			संयुक्त मंत्री
४—श्री मधुकर दिघे			,,
५—श्री रामसागर मिश्र			,,
६—श्री अर्जुन सिंह भदौरिया		(इटावा)	सदस्य
७—,, चन्द्रबली सिंह		(देवरिया)	,,
८—,, काशीनाथ मिश्र		(बलिया)	,,
९—,, दलश्रृंगार दूबे		(गाजीपुर)	,,
१०—,, विश्रामराय	M. L. A.	(आजमगढ़)	,,
११—,, राजनारायण	M. L. A.	(बनारस)	,,
१२—,, प्रभुनारायण	M. L. C.	(बनारस)	,,
१३—,, रामनारायण त्रिपाठी	M. L. A.	(फैजाबाद)	,,
१४—,, सिब्ते मुहम्मद नकवी		(फैजाबाद)	,,
१५—श्री उग्रसेन सिंह		(देवरिया)	सदस्य

१६—,,	चन्द्रशेखर तिवारी	(कानपुर)	,,
१७—,,	बलवान सिंह	(,,)	,,
१८—,,	विमल मेहरोत्रा	(,,)	,,
१९—,,	मुल्कीराज	(सहारनपुर)	,,
२०—,,	शमसी मीनाई	(गोण्डा)	,,
२१—,,	अध्यात्म त्रिपाठी	(बस्ती)	,,
२२—,,	देवेन्द्र सान्याल	(अलमोड़ा)	,,
२३—प्रो०	वासुदेव सिंह	(प्रतापगढ़)	,,
२४—श्री	रामसेवक यादव	(बाराबंकी)	,,

गाजीपुर सम्मेलन हर दृष्टि से एक सफल सम्मेलन रहा। राष्ट्रीय कार्यसमिति ने अवैधानिक रूप से इस पर रोक लगाकर इसको असफल बनाना चाहा। आचार्य नरेन्द्रदेव जी का इस सम्मेलन को बहिष्कार करने का आदेश भी उसी तरफ कोशिश थी। कुछ जिले के तथाकथित नेताओं के वक्तव्य और इन सब के बावजूद आचार्य नरेन्द्र जी का नाम लेकर जिलों २ में घूमकर इस सम्मेलन में न जाने की अपील की गई। गाजीपुर में तो आचार्य जी के नाम का दुरुपयोग करने के साथ २ यहाँ तक प्रचार किया गया कि यदि कोई नागरिक आम सभाओं में जायगा तो वहाँ दंगा होगा और लोग गिरफ्तार होंगे। साथ ही जो लोग चंदा की रसीदें ले गये थे उनमें से कुछ लोगों ने चंदा वसूल करके कापियों का हिसाब तक न दिया और कुछ पैसा कोषाध्यक्ष महाशय (एडहक कमिटी के सदस्य) के पास ही रह गया। इन सब प्रयासों के बावजूद भी अधिक संख्या में प्रतिनिधि आये और गाजीपुर जनता ने सहयोग दिया।

अगर पिछले वर्ष के सम्मेलनों को देखा जाय तो पता चलेगा

कि तुलनात्मक दृष्टि से इस सम्मेलन को कितनी सफलता मिली।

स्थान	प्रतिशत सदस्य उपस्थिति	साधारण सदस्यता संख्या	प्रतिनिधियों की उप० की संख्या
मुजफ्फरनगर	·२६२	४०,०००	१०५
आजमगढ़	·५०६	५२,०००	२६५
निगोहाँ (लखनऊ)	·२२०	६५,०००	१४३
गाजीपुर	·८०७	४२,०००	३८७

मुजफ्फरनगर व आजमगढ़ सम्मेलन सोशलिस्ट पार्टी के सम्मेलन थे। आजमगढ़ सम्मेलन आम चुनाव के ठीक पहले हुआ था इसलिये काफी उत्साह से लोग गये थे। निगोहाँ सम्मेलन में सदस्यता अधिक इसलिये थी कि उस समय सदस्यता शुल्क आठ आने थी। इस वर्ष सदस्यता शुल्क एक रुपया थी जिससे कि सदस्य कम बने। जहाँ प्रजा सोशलिस्ट के प्रथम सम्मेलन निगोहाँ में ·२२०% प्रतिशत लोगों ने भाग लिया वहाँ गाजीपुर में ·८०७ प्रतिशत प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

एक हजार से अधिक सदस्य बनाने वाली जिला व शहर शाखाओं में आजमगढ़, बाराबंकी, बलिया, बरैली, बस्ती, बनारस जिला, देवरिया, इटावा, फरुखाबाद, फैजाबाद, गोरखपुर, गाजीपुर, जौनपुर, कानपुर जिला, कानपुर शहर, मथुरा, प्रतापगढ़ इत्यादि १७ शाखायें होती हैं। इनमें से बरैली, फरुखाबाद और मथुरा से कोई प्रतिनिधि न आ सके। परन्तु आगरा व बरैली पार्टी के जिलामंत्री साथी बृजराज सिंह तथा कुंवर मोहनस्वरूप क्रमशः तथा आगरा किसान पंचायत के अध्यक्ष व अरदाया कांड के नेता स्वामी विश्वेश्वरनन्द ने सम्मेलन के लिये शुभसंदेश भेजा है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले से सम्मिलित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या व प्रत्येक जिले के प्रमुख साथियों के नाम विस्तृत सूची से ज्ञात हो जायेंगे। इससे भी स्पष्ट हो जायगा कि प्रमुख जिलों के प्रमुख साथियों ने गाजीपुर सम्मेलन में भाग लिया।

१. स्वामी भगवान—प्रधान मंत्री हिन्द किसान पंचायत
२. साथी राजनारायण—नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश
३. रामनारायण त्रिपाठी—उपनेता ,, ,,
४. रंगनाथ शर्मा—प्रधानमंत्री, समाजवादी युवक सभा
५ रामसागर मिश्र—संयुक्त मंत्री हिन्द किसान पंचायत उत्तर प्रदेश
६. गनेश त्रिपाठी—संयुक्त मंत्री, हिन्द मजदूरसभा, उ० प्र०
७. शमसो मीनाई—सभापति, समाजवादी यु० स० उ० प्र०
८. विजयकुमार—प्रधानमंत्री ,, ,, ,, ,,

इसके अतिरिक्त साथी दानसिंह नैनीताल, ईश्वरीसिंह प्रधान मंत्री, हिन्द किसान पंचायत उत्तरप्रदेश बुलन्दशहर, स्वामीनारायण जिला मंत्री फतेहपुर ने शुभकामना का संदेश भेजा था।

उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त साथी **सईद उल्लाखाँ रजमी** एम. पी. व **एजाज हसन** क्रमशः भोपाल प्रान्तीय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष व कार्यसमिति के सदस्य, **साथी पी०वी०जी०राजू** एम. एल. ए. नेताविरोधी दल आंध्र व श्रीमती **कुसुम राजू** एम. एल. ए. आन्ध्र, साथी **सुरेन्द्रकुमार सक्सेना** दिल्ली पार्टी के नेता, साथी **सच्चिदानन्द** बिहार युवक सभा के नेता, **प्रणवकुमार चाट्टोपाध्याय**

व बिहार पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन को अपनी शुभकामनायें स्वयं इस सम्मेलन में उपस्थित होकर दीं।

यह रिपोर्ट एडहाक कमेटी का मुँहतोड़ जवाब है। इससे राष्ट्रीय कार्यकारिणी बेनकाब होगी और उसकी तानाशाही शकल जनता के सामने आवेगी। जनता फैसला करे कि दोषी कौन है।

डा० राममनोहर लोहिया का वक्तव्य

भारत की जनता द्वारा समाजवादी नेतृत्व के कार्यों के प्रति मौन या उनकी स्वीकृति प्रजातंत्र और समाजवाद के लिए निम्नलिखित कारणों से घातक होगा:—

१—राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा विज्ञप्त मुअत्तली और निषेधाज्ञा विधि और आचार संहिता के विरुद्ध हैं और यदि उनका विरोध नहीं किया जाता, तो वे राजनीतिक दलों के आंतरिक प्रजातंत्र के हनन द्वारा वाह्य प्रजातंत्र के नाश में सहायक होंगे क्योंकि—

(क) ये कार्य किसी वैधानिक धारा या नियम के अधीन नहीं किए गए, बल्कि आचार संहिता के अंतर्गत, जो कि बिल्कुल न्याय परक नहीं। गीता निस्संदेह अपराध संहिता से उच्चतर विधि है, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति उसके अधीन कानूनी कारवाई की कल्पना नहीं कर सकता;

(ख) आचार संहिता की दसवीं धारा, जिसके अंतर्गत ये कारवाइयां की गई हैं, का संबंध एक दूसरे के प्रति "शिकायतों" से है, जैसे गबन अथवा चुनाव जिन्हें पार्टी के सदस्य, सार्वजनिक रूप में व्यक्त करने की बजाय उचित कमेटियों के समक्ष ला सकते हैं। यह धारा बुरी तरह से फैलाकर नीति संबंधी आलो-

चनाओं, जो सार्वजनिक न बन सकने के कारण प्रजातंत्रीत महत्व को खो बैठती हैं, को ढकने का काम करती हैं;

(ग) कार्यसमिति को चुने हुए प्रतिनिधियों के सम्पूर्ण सम्मेलन को निषिद्ध/करने का कोई भी अधिकार विधान द्वारा प्राप्त नहीं। यह एक अनहोना कार्य है और सहज बुद्धि इसे उस कुत्ते की भांति समानता देगी जो हाथी को भूंककर अपने अधीन रखने का यत्न करे;

(घ) इतने भयंकर प्रकार की कार्यवाही न ली जाती यदि "अपराधी" खेद प्रकट करें। 'अपराध' का यदि उसे ऐसी संज्ञा दी जाय अन्य प्रकार से भी प्रदत्त दण्ड के अनुपात में नहीं ठहरता और उस आजीवन कारागार के सदृश है जो किसी व्यक्ति को अश्लील वक्ता पर सड़े टमाटर फेंकने पर दिया जाय। कार्यसमिति स्पष्टतया सम्मान या नीति अथवा कुछ ऐसे अभीष्ट की खोज में थी।

(ङ) मुअत्तल सदस्य प्रतिनिधि-अधिकार से वंचित किया जा सकता है और उनको दण्ड देना जो उन्हें भाषण के अधिकार का अवसर देते है प्रातशोधात्मक है;

(च) उत्तर प्रदेश कार्यसमिति और सम्मेलन के विरुद्ध कार्यवाही दो प्रस्तावों को, जिनमें से एक का प्रारूप उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो बाद में नामांकित समिति के अध्यक्ष हो गए, पारित करने के परिणाम-स्वरूप की गई। अत्याचार ने सदैव अपने ढंग के अनुशासन की सिद्धि के लिए कार्यकर्ता का प्रयोग किया है। अनियमित ढंग से अधिकारारूढ़ समिति के तीन अच्छे व्यक्तियों ने त्यागपत्र दे दिया है और उनमें से दो, विश्रामराय एम० एल० ए० और अर्जुनसिंह भदौरिया नई कार्यसमिति के सदस्य चुने जा चुके हैं। राष्ट्रीय कार्य-

कारिणी निर्वाचित समितियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में विरोध को प्रश्रय दे रही है और गाजीपुर सम्मेलन के विरोध में विद्रोही समिति को नियुक्त कर राज्यस्तर से जिला स्तर तक उतर आई है;

(छ) अखंडित स्पष्टीकरण के आधार पर जो पहिले किया गया है उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि अपने प्रस्ताव को वापस लेने, निमंत्रण को समाप्त करने और अध्यक्ष द्वारा खेद प्रकट करने को तैयार थे यदि अखिल भारत भारतीय अध्यक्ष मुअत्तल बम्बई के मामले का पुनर्विचार करें। इस वास्तविक समर्पण ने मुझे चकित कर दिया जब मैंने इसे सुना, लेकिन फिर भी कतिपय व्यक्तियों ने इसकी स्वीकृति की हालत में पार्टी से त्यागपत्र देने की धमकी दी।

(ज) उसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने, जिसने वैधानिक असमर्थता के आधार पर बम्बई कारखाई का पुनर्विचार करने से इन्कार किया, अनुशासन के आंध्र के मामले पर पुनर्विचार किया, और इससे यह सिद्ध किया कि मामले का संबंध अनुशासन से नहीं बल्कि नीति से था;

(झ) ऐसी लज्जाजनक काररवाइयां इसलिए संभव हुई कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस सामान्य, किन्तु भ्रामक विश्वास पर आस्था रखती है कि अनुशासन का अर्थ ऊंची आज्ञाओं का पालन मात्र है। विश्वास की ऐसी निरंकुशता और बहुमत का शासन प्रजातंत्र को सबसे खराब राजतंत्र से भी खराब दानव में परिणत कर देगा। उच्च तथा निम्न समितियां और व्यक्तियों को आवयिक विधि अर्थात् विधान के अन्दर कार्य करना चाहिए वर्तमान सघर्ष में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पराजय कलेक्टर

पटवारी सिद्धान्त की पराजय का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो वर्तमान में देश की राजनीतिक पार्टियों के उच्चतर और निम्नतम समितियों के संबंधों का निर्देशन करता है और उनका गला भी घोंटता है। कार्यकारिणी की जीत प्रजातंत्र के विनाश में एकतंत्रीय नियंत्रण को फिर से लादने और विरोधी तत्वों को अपने पार्टी नेताओं को आतंकित कर आत्मसमर्पण करने में सहायक होगी।

२—अनुशासन के नकारात्मक पहलू से अत्यधिक पराभूत होना सकारात्मक अनुशासन के ढांचे को बरबाद करना है और इससे नकारात्मक अनुशासन का ढांचा भी दुर्बल होता है क्योंकि—

(क) नीचे से ऊपर अर्थसंचय के क्रियात्मक अनुशासन को सुदृढ़ पुष्ट करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता और समाजवादी दल दीनों से मत और धनवानों से द्रव्य प्राप्त करने के विभक्त (हीन) मस्तिष्क द्वारा दुर्बल होता जाता है;

(ख) क्षेत्र समितियों और प्रारम्भिक युनिटों की सभाओं को संगठित करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। विधान के अनुसार प्रारम्भिक युनिटें वर्ष भर में चार बार अवश्य बैठकें बुलावें, और क्षेत्र समितियां छ बार; किन्तु समाजवादी नेतृत्व सदा सर्वदा से अनुशासन और विधान की आवश्यकता को ठुकराता आ रहा है;

(ग) झुंड-सदस्यता से मानवीय सदस्यता बदलने का कोई यत्न नहीं किया गया। नेतृवर्ग, धन, सुषुप्त समितियां

और भेड़ियाधसान सदस्यता से जनचेतना जागृत करना असंभव है;

(घ) नेताओं के रूप में भोंडा निजी वाद व्याप्त है जो अपने आदमियों को संसद और विधान सभा के उम्मीद वारों के लिए चुनवाना चाहते हैं। अपने महत्व के अनुरूप नेतागण अपने दावों का संतुलन करते हैं और यदि कोई इस स्वार्थवाद को स्वीकार नहीं करता और सामुहिक निर्णयों को उचित कमेटियों द्वारा प्रोत्साहन देना चाहता है तो उसे भेडिया झुंड नेतागण का व्यक्तिवादी कह कर बदनाम करते हैं;

(ङ) 'नाम जाप' और अंधाधुंध सामुक्तिगान के गुण को बढ़ावा दिया जाता है, और कार्य और विचार को हतोत्साह किया जाता है;

(च) निषेधात्मक अनुशासन के संबंध में कोई काररवाई नहीं की गई, जैसे INTUC भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कमेटी या दूसरे सदृश अमैत्रीपूर्ण संगठनों से संबंध या अभिनवीकरण, भाषापरक राज्य तथा अन्य स्वीकृत नीतियों के विरुद्ध संसद में भाषण

(छ) पार्टी के उन मान्य प्रतिनिधियों के विरुद्ध, जिन्होंने कांग्रेस दल से किन्हीं शर्तों के माने जाने की दशा में संयुक्त सरकार बनाने के लिए सार्वजनिक वचन दिया था, कोई अनुशासन की काररवाई की कल्पना नहीं की गई। और न तो उनको चेतावनी ही दी गई। उन्होंने संयुक्त मंत्रिमंडल चाहा था जब कि कांग्रेस केवल सहयोग की अपेक्षा करती थी;

(ज) जो बातचीत को प्रोत्साहन और गालीगलौज को निषिद्ध

करना चाहते हैं स्वयं सबसे बड़े निंदक हैं क्योंकि वे अपने विरोधियों की बात को गाली और अपनी गाली को उचित बात समझने की भूल करते हैं अंत में संपूर्ण समाजवादी चोटी के नेताओं को हमारे मनोभाव (नीयत) पर लिखित व्यक्तिगत और ईर्ष्याजन्य आक्रमण का दोष लगाता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ कि वे मेरे द्वारा एक भी लिखित वाक्य नहीं पेश कर सकते जिनमें मैंने किसी व्यक्ति और उसकी नीयत पर हमला किया हो। मैंने उनके खिलाफ कभी भी काररवाई की मांग नहीं की है और न भविष्य में करूंगा क्योंकि आचार्य नियम के शब्द नापसंदगी के कारण हो सकते हैं लेकिन कानूनी कारवाई के नहीं।

३—अनुशासन और प्रजातंत्र के दोषयुक्त विचार समाजवादी नेतृत्व के कर्म विचार, और संगठन के तीनों क्षेत्रों में संपूर्ण असफलता के आवरण हो जाते हैं, क्योंकि—

(क) आन्ध्र सेक्रेटरी और अखिल भारतीय पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा का अंतिम पर्दा फाश प्रकट करता है चुनाव समझौता के लिए आंध्र कांग्रेस के प्रधान के साथ भेंट की खोज थी और हुई भी। पार्टी नीति का इतना स्पष्ट उलंघन का सीधा कारण कांग्रेस पक्षी मनोभाव (मिजाज) है, जो लगातार चुपके चुपके पैदा हो रहा है। इन स्पष्टोक्तियों (स्पष्टीकरणों) में केवल एक बात विवादग्रस्त है कि आन्ध्र सेक्रेटरी वार्ता का प्रारम्भिक और अखिल भारतीय अधिकारी दोषपूरक या अखिल भारतीय अधिकारी आरंभक और आन्ध्र सेक्रेटरी पार्टी नीति का सबसे दोष युक्त उलंघन का कुशल निषेधक;

(ख) अप्रैल और सितंबर १६५४ के बीच जनता का मिजाज उठ रहा था जिसका अनिवार्य प्रभाव सारे देश पर पड़ता जिससे दुख के खिलाफ राष्ट्रव्यापी संघर्ष १६५५ के आरंभ में चलाया जा सकता था। संकुचिततापूर्ण प्रशासकीय और अमानवीय दृष्टिकोण जिसे समाजवादी नेतृत्व ने पुलिस द्वारा गोली चलाने पर अख्तियार किया समाजवादी संगठन पर न केवल अलाभकर कलंक लगाया बल्कि राष्ट्रव्यापी जाग्रति की संभावना का प्रभावशाली ढंग से गला घोंट दिया;

(ग) विलीनीकरण, संयुक्त सरकार, शत के साथ संयुक्त सरकार और सहयोग के चारों विचार, प्रत्येक एक दूसरे से क्रम में अधिक भयंकर हैं समाजवाद की पार्टी को प्रभावतः पंगु बना रहे हैं। भविष्य की नीयत की बहस से वर्तमान व्यवहार को धुंधला नहीं करने देना चाहिए, वर्तमान लकवा फैलाने के दोष लोग वास्तव में सैद्धान्तिक उग्रवादिता और पार्टी की नीति की दुहाई दे सकते हैं।

(घ) संसद वह वृद्धा स्त्री हो गई है जो अपने प्रेमी प्रधान मंत्री के मुसकान की सतत प्रतीक्षा में हो। बेकारी, बेदखली, मूल्य असंतुलन और अत्याचार विद्यमान है, लेकिन कोई भी जनान्दोलन नहीं जाग्रत कर रहे। अन्याय के विरुद्ध कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय संघर्ष की तैयारी नहीं कर रहा है। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा के सभी मोरचों पर अवश्य सक्रिय होना चाहिए। विशेष रूप से मैं देहरी दालमियाँ नगर क्षेत्र प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की प्रशंसा करता हूँ जिसने न केवल कमेटी की बैठक में बल्कि सार्वजनिक सभा में कई हजार लोगों ने उपस्थित होकर तानाशाही राष्ट्रीय कार्य

कारिणी के हटाने की माँग के प्रस्ताव पास किया। देश की प्रत्येक क्षेत्र समिति अवश्य सभा बुलाकर बहस करे और प्रस्ताव पास करे। यह जनता का राजनीति में हिस्सा लेने की जबरदस्त शुरुआत होगी। इसके अतिरिक्त बिहार की समाजवादी पार्टी, जहाँ तक उसके सर्वसाधारण कार्य-कर्त्ता और मजबूत संगठन का संबंध है, देश में सबसे अच्छी शाखा है, जो पिछले कतिपय वर्षों में अयोग्य नेतृत्व के कारण प्रतिगामिता का गढ़ बन गई थी। गढ़ तेजी से ढह रहा है और संभव है बिहार आश्चर्य जनक डबल मार्च (द्विगुणित वेग) प्राप्त कर सके। यदि ऐसा हो तो कुछ आशा अभी भी है कि सारे देश में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का सुधार हो सकता है और आगामी राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद इसके जीवन का नया पहलू आरंभ हो सकता है।

INAUGURAL ADDRESS

by

Com. Madhu Limaye.

"The future of the Socialist movement has been put in grave jeopardy by the series of illegal end authoritarian actions of the ruling group within the PSP. The issue before the party was very simple ; co-existence or disruption. By starting a process of suspension the executive has chosen the path of disruption. No socialist can take this lying low. It is for us to lift the movement from its present morass.

"The party of Indian socialism has already witnessed three phases; the CSP, the SP, and the PSP. It does not matter whether its present form survives. The essential thing is that the quest and the struggle for a new social order that has propelled all active socialists through these various phases continues with renewed vigour and determination.

"Shorn of the verbiage about propriety, discipline and constitutional forms the basic differences in the party boil down to this. Whether the party of socialism should function as a constructive yet militant opposition or should become the ruling party's pliant instrument. The approach of the now famous Allahabad statement is one of militant opposition. Barring a few couragous co-operationists almost every one swears by it. However this has become a ritual and many of those in authority while paying lip sympathy to it actually persue a do nothing policy in regard to political and economic issues and of active hostility on the so called discipline front.

"It is no accident therefore, that the Kerala Ministry which recommended extention of preventive deten-

tion, opposed trade unionism in state industries and alternately flirted with the Congress and the Communist parties won a certificate of good and dignified conduct from the executive. Contrary to the letter and spirit of the policy statement an electoral adjustment with the ruling party was encouraged by some highly placed persons in Andhra Elections. That if it did not materialise is another matter. It is not unusual either that the public denunciation of the Allahabad as "obsolete" and vilification of party comrades was tolerated and suspensory actions initiated against those who opposed the policy of co-operation. On the one hand batches of partymen demoralised by the co operationist propaganda are jumping to the Congress band-wagon, on the other hand there is indecent haste to throw out people wh › are anxious to stem the rot in the party. The Executive's contribution to the Manipur struggle was its denunciation of the person who sought to intensify it and to the Goa struggle, dissolution of the eleeted committee of the largest state branch of the party.

"The directive of the ruling group that no party member would attend the Samajvadi Yuwak Sabha conference because it is to be presided over by a suspended member, the circular letter demanding in the name of the Chairman that the Chairman of the biggest PSP unit be suspended, all these are signs of the growing totalitarian tendences within the party.

"The fact is that under the new constitution adopted at Indore last year, the Bombay Committee has the status of a District Branch and is not at all competent to suspend any member. Besides the action against me was taken on the strange ground that I held a press conference, without indicating what said or done at the press conference, violated which article or rule of the constitution. The action against your Chairman under a code of conduct which has no legal validity is also unconstitutional. A clause which was meant to cover allegations against misappriopration of

public funds, bogus membership etc. has been construed as a ban on all criticism of executive decisions. This is extraordinary, especially when it is remembered that the Bombay Committee had publicly criticised the executive decision on Travancore Cochin electoral adjustment and the Maharashtra party the formation of the parliamentary bloc with More as its general secretary. All these executive decisions could be challenged in a Court of Law but normally one does not do it in a political party. The normal method would be to let the revolt against the executive high handed spread throughout the country.

"India is alowly drifting towards a one-party state. The Sarvodaya talk about the no-party state, the theory of His Majesty Nehru's loyal and emasculated "opposition" seeking areas of agreement and electoral adjustment with the ruling party, and the communist soft padling of Congress injustices in the name of a peace policy, all these are driving us incessantly towards a total state. The first five year plan has not solved the problem of growing unemployment, poverty and inequality nor will the second plan do that. The first plan, however, has paved the way towards centralisation of economic power and the second and the third plans will complete the process. That must spell disaster for the millions and social disruption and tensions all round.

"The need for a party with a clear decentralist, socialist programme, championing the cause of the oppressed is very great. We have to be that party, no matter what the price be. The following programme of work suggests itself ;

(1) Top priority should be given to socialist youth organisation on the basis of contructive work, social reforms and ideological training ;

(2) Workers' struggles against retrenchment and increase in work load as in Kanpur ;

(3) Agitation among educated youths against the growing unemployment ;

(4) Campaign against falling agricultural prices and for parity ;

(5) Active resistance to all unjust tax burdens likely to be imposed on the people during the second plan ;

(6) Agitation for more powers to the local bodies.

Finally I would like to say a word about the Goa movement. There is a danger of its continuing under the tutlaege of the Prime Minister. It must throw off the tutel and develop as a genuine popular movement.

PRESIDENTIAL ADDRESS.

by

Gopal Naryan Saxena

We are meeting here to-day under the shadow of a barbaric persecution. In its uncommon zeal for witch hunting, a committee of twenty five persons has gone to the length of banning a Conference of several hundred delegates representing 30,000 and more socialists. The enormity or this unconstitutional act has helped me in overcoming my diffidence about presiding over this conference from which in view of the suspendory action taken on me, I would otherwise have desisated. I am happy that all of you by assembling here have demonstrated that the Socialist movement yet retains the capacity of resisting injustice whether internal or external.

Some have said that the false cry of ideological differences has been raised to cover up indiscipline but I wish to assert that the false cry of indiscipline has been raised to cover up ideological and policy differences. It is too late in the day for these gentlemen to deny the existence of ideological and policy differences in the party. The whole country knows of them. What is not so commonly known is the foul practice of swearting, allegiance to the abstract enunciation of a policy and defeating all concrete applications of that policy to given situations. The latest cry of indiscipline is another attempt in the same direction. It admirably serves the purpose of eliminating unwanted persons without entailing the risk of facing squarely the ideas that they stand for.

What after all is discipline. Is it an instrument to build up an organisation for the futherance of an idea or is it a weapon for the perpetuation of authority and

the silencing of dissident voices. I should like to state that in relation to political parties discipline has both a positive and a negative aspect. In the positive sphere it means the execution of acts designed to achieve one's objective. In the negative sphere, it means the non-doing of acts which are likely to help other parties against one's own. These tests should now enable one to find out the real offenders of discipline in the Praja Socialist Party.

There are other important questions relating to procedure jurisdiction and the internal relationship of committees and persons. Even servants can sue, their employers for wrongful dismissal. Subordinate committees or persons should not be so regarded that superior bodies can do what they like with them. Even superior persons and committees must operate within the law according to prescribed rules and within the limitations of their authority. That is the essence of democracy. The majority in a democracy is not the absolute morarch to act as it wills. When a superior committee in a political party acts arbitrarily and outside its prescribed authority, democracy requires that its act should be challenged. That is particularly necessary in India where the people cling to the disastrous belief in heirarchy in considering any lower committee as a Patwari committees should we win this battle in the P. S. P. The Indian people as a whole will have won a great right political parties in the country will thenceforth have to practice internal democracy.

Yet another question is of the equitable correspondence of offence and punishment. Hands were cut off for the offence of stealing in certain periods of ancient India. While some may romanticise that law, any sensible person would call it grievous assault and inflicting of injury. There was no offence done in inviting a person to speak, even a person who has been suspended from membership, suspended member has a right to speak although his right to represent is withheld from him. Even those who would consider it an

offence would certainly not call it a major offence and to award a sentence of death for a small altercation would be unjust and barbaric.

I should now like to briefly touch on the question of our relation with the party in power. This question has been discussed at length in the party and outside and it is unfortunate that even after several definite verdicts from the party membership some people are still able to keep this question alive and open. There have been repeated announcements from some persons that they do not intend to go over to the Congress and from some others that no one in the party thinks of joining the Congress. In the first place I would like to say that in spite of these pronouncements, people are going over to the Congress party and in the second place that whether some are or are not thinking of joining the congress is a matter utterly irrelevant and unimportant. In fact no one has accused these persons of these intentions.

The essential question is not in relation to some future and distant co-operation or otherwise with the Congress party. The deciding question relates to the present behaviour of opposition parties. What they might do in the future is a secondary question but what they are doing in the present is a primary and important question. All opposition parties keep mum in relation to the big problems and criticise the Government on minor issues. That keeps up the appearance of opposition but achieves the substance of Friendship I want my party, the Praja Socialist Party, not to keep mum in parliament or assemblies over the big questions but to kick up such a din in relation to unemployment, falling agricultural prices, dental of civil liberties and the like that the people as well as the government sit up and take note. There is no opposition party in the country today and what we are seeking to do in U. P. has only one aim and that is to make the PSP into an organisation that will effectively oppose when

out of office and truly reconstruct the country on socialist lines when in government.

The opposition in assemblies and parliament ought vigorously to reflect the miseries as well as the aspirations of the people. Parliament and assemblies in India are suffering from pernicious anaemia and only that party can revive them whose legislators are not tied up with the party in power. I have already said that the present trend in the party leadership, deliberately or otherwise is to shelve the burnning issues of the day. The deeds of the National Executive can at best achieve the result that socialist intellect may be wed to 'Congress power' that a couple of hundred socialists all over the country, may find their places in legislature and some in ministers for rebuilding the country. I should like to ask a qu stion. Are we a party of two hundred or so leaders, perphas eminently able, whose talents are a still unused or are we a peoples' party out to change the face of India.

On the reply that you give to this question depends the future of the socialist movement in India, once we are clear about this objective, the P. S. P. would find no difficulty in organising the peoples' will against Congress misrule, unleass a nationwide peoples' movement against unemployment and corruption and thereby win the country's support to send upright milliant people to the ligislatures and to power.

RESOLUTION PASSED BY THE SECOND ANNUAL CONFERENCE OF THE PRAJA SOCIALIST PARTY (U.P.) AT GHAZIPUR

This Conference of the U. P. Praja Socialist Party congratulates socialists of Uttar Pradesh on the fulfilment of their resolve to defy the National Executive's undemocratic and anti-socialist fiat. The National Executive disregarded all rules of discipline and constitution, deprieved suspended members not only of right of representation but of speech, tried to gag ideological and policy debates by introducing an involved and perverse interpretation of the clauses of the Party Constitution and attempted not only to suspend the Executive of the State in Uttar Pradesh disregard of constituional powers and jurisdiction but to ban and sabotage its annual conference. The State Executive acted with great tolerance and accommodation but the attempts of the National Executive have shown that it was in a futile search of false prestige and totalitarian powers. To bow to such methods would have meant the strangulation of the newborn child of socialism and democracy, just as socialists of Uttear Pradesh have by resisting them deepened and strengthened the foundations of internal democracy in political parties.

In the opinion of this Conference, if some can take cover behind ideological differences in order to hide their indiscipline, others can, and are raising the slogan of indiscipline in order to obscure and settle ideological and other differences. Without a doubt differences of ideas, policy, action and outlook have during recent times crossed legitimate bouuds in the Party of socialism and it is essential to clarify them through action and debate, but to deny their existence on the one hand and to settle them through disciplinary actions on the other is not only untrue but fatal. In any

organisation discipline should be directed towards the realisation of objectives and in accordance with rules. The National Executive neglecting the constitution and rules, has taken refuge behind the common but false conception that subordinate committees and persons should obey superior committees and persons. In fact, democratic organisation and discipline can never be based on such Patwari committees and all persons and committees, whether superior or subordinate should act within the limitations prescribed by rules. The U. P. Praja Socialist Party deserves to be congratulated by the people in so far as it struck hard on this bureaucratic method of organisation and discipline even at the cost of injuring itself badly.

Discipline in both its positive and negative aspects is the skeleton to support the flesh of organisation. Members of a Party ought never to give public expression to mutual disputes relating to internal elections or charges of malpractices on each other, nor should they seek election against each other outside the Party. Those who do so should be disciplined. But words, no matter how strong, used during ideological debates should never be made the basis of any disciplinary action, although any displeasure at such words can be expressed through personal behaviour. Any disciplinary action on such grounds leads to partiality as there generates a tendency to exaggerate the apparent harshness of one side and to overlook the wrongs of the other. Democracy is shelved and with it split of the Party becomes inevitable. There is even greater need of positive discipline and it can be enforced not on the basis of individual opportunism but of principles. In such a discipline there can be hardly any place for opportunists who support the resolution of the State Executive and when it results in the suspension of that Executive, join the new committee dictatorially foisted by the National Executive. Besides consistency in ideas and action, it is also necessary to observe strictly the constitutional provisions regarding membership and committees. Elections on party ticket shoul only be

permitted at places where committees and candidates satisfy constitutional requirements. Socialists must now lose no time in understanding that discipline is impossible so long as the hope of financial assistance from the top remains.

This Conference of the Uttar Pradesh Praja Socialist Party considers it essential to particularly emphasize these principles of organisation in the present situation of the country. Unemployment and ejections are on the increase, agricultural prices are going down in contrast to increasing or stationary industrial prices and tax burdens, the economic condition of the people is deteriorating in spite of apparent, artificial, or long range planning of national reconstruction and the people are being subjected to unprecedented police terror. The general elections are drawing near, and while the ruling party is at least apparently gaining strength, the opposition parties seem to be weakening. In this hour of co-existence of mounting misery and diminishing opposition, the confusion of policy prevailing in the Praja Socialist Perty is most unfortunate. Many different persons have been putting forth ideas of merger with the Congress Party, coalition government, coalition governments on specific conditions and co-operation as also taking active steps towards them but it has become unnecessary to discuss them. Whatever may be the future consequences of these ideas and connected events, in the present they are succeeding in paralysing the Praja Socialist Party. The real issue is obsecured by the fruitless controversy on whether any person or group of persons in the Praja Socialist Party would in the future join the Congress. The issue is whether and to what extent the Praja Socialist Party is fostering and furthering militant or paralysed socialism. The futile attempt to wed socialist intellect to Congress power for national reconstruction is helping the paralysis of socialism and trying to make the Praja Socialist Party a party of two-to-three hundred successful leaders or legislators instead of a peoples' party. With these ideas and the advent of elections, the intoxication of

political opportunism which helps to maintain the superficial unity and internal discord of the Party and continually allures with the prospects of success in elections without ever winning them is bound to increase. Politics in India is a huge bog and without driving into it stakes of principles and corresponding action and organisation, neither immediate victory nor the building of socialism is possible. It is necessary to offer steady and continual opposition to increasing misery and organise peoples movements based on such policies as "employment or unemployment allowance", "no increase in taxation without price parity" and "no ejectments". When necessary, unjust laws and administrations should be disobeyed and defied.

All members and committees of the P. S. P. throughout the country who want militant socialism to win against paralysed socislism are now charged with the duty to make their Party a fit instrument of construction and struggles and to promote an atmosphere healthy for active socialism by undertaking the mutually complimentary tasks of organisation and political training.

This Conference calls upon all socialists of the country to :

1. Organise the Party in accordance with the constitutional provisions relating to membership and committeess.
2. Engage in constructive work.
3. Organise sustained agitations and, whenever necessary, peaceful struggles against injustice..
4. Work for the enhancement of peoples courage on the basis of civil disobedience.
5. Form branches of functional organisations such as Hind Kisan Panchayats. Hind Mazdoor Sabhas and Samajwadi Yuwak Sabha and through them intensify peaceful class struggle, and demand for the constitutional relationship between these organisations and the Party.

6. Arrange training camps for workers and try to orientate common political propaganda towards the objective of the Party.

7. Build up candidates for legislatures, trained in principles and policies and strong committees to check, support & when necessary replace them.

This Conference urges upon socialists of this state not to recognise and co-operate with the ad-hoc committee formed by the National Executive in uttar disregard of democratic practice. The National Executive has started factionalism and the formation of a new party in Uttar Pradesh and it is the duty of all socialists to defeat them in this purpose. This conference requests all members of the P. S. P. and all committees in the country down to the constituency level, to debate on this resolution, form opinions and express it through resolutions. It further asks them to oppose the National Executive and demand its removal.

Dr. Ram Manohar Lohia's Views.

Silence on or acquiescence in the acts of socialist leadership by the people of India will spell disaster to democracy as well as socialism for the following reasons :—

(1) Suspensions and bans promulgated by the National Executive of the Praja Socialist Party are in violation of law as also of good conduct and, unless defied, will help ruin outward democracy by destroying internal democracy of political parties because :—

(a) these actions were taken not under a constitutional clause or rule but under a code of conduct, which is entirely non-justiciable. The Gita is certainly a higher law than the penal code but no sane person would contemplate legal action under it ;

(b) clause X of the code of conduct under which these actions have been taken relate to "complaints" against one another, such as concerning defalcation or elections, which members of the Party may bring before the appropriate committee instead of ventilating them publicly. This clause has been mischievously stretched to cover policy criticisms, which lose all democratic meaning unless made publicly ;

(c) the constitution contains no provision whatever for an executive committee banning an entire conference of elected delegates. Such an act is unparalleled and common sence would like it to the dog trying to bark the elephant into submission

(d) actions of such terrifying proportions would not have been undertaken if the "offenders" had expressed regret. Even otherwise, the offence, if such it may be called, bears no proportion to the punishment inflicted

and is like the award of life-long imprisonment to a man who might have thrown a rotten tomato at a vulgar speaker. The executive committee was obviously seeking prestige or policy or some such end ;

(e) suspended members may lose their right to represent and to punish those who give them an opportunity for the right to speak is vengeful ;

(f) action against the U. P. Executive and Conference followed upon the passage of two resolutions; one of which was drafted by the man who later became the Chairman of the nominated committee. Tyranny has always used agents provocateurs as agencies for achieving its own brand of discipline. Three of the best men on the usurper committee have since resigned and two of them, Vishram Rai, M. L. A. and Arjun Singh Bhadoria, have been elected on the new executive. The National Executive is trying to foster a rebellion in U. P. against elected committees and has already travelled from the state level to that of the district by appointing a rebel committee for Ghazipur ;

(g) on the basis of unchallenged disclosures already made, U. P. representatives were willing to rescind their resolutions, cancel their invitations and have their Chairman express regret, if the all-India Chairman agreed to reconsider the case of the suspended Bombay member. This virtual surrender left me gaping when I heard of it, but it was also met by the threat of some pessons to resign from the party in the event of its acceptance :

(h) the same National Executive which refuses to re-open the Bombay action on ground of constutional incompetence reopened the Andhra cases of discipline, thereby proving that what was involved was policy and not discipline ;

(i) such shameless acts were possible because the National Executive banked on the popular but erroneous belief that discipline meant obedience to higher

orders. Such absolutism in beliefs combined with majority rule must inevitably turn democracy into a monster worse than the worst monarchy. Higher as Higher as well as lower committees and personnal must operate within the limitations of the organic law, that is the constitution. In the present struggle, defeat of the National Executive would pave the way for defeat of the collector-patwari principle that at present regulates relationships among lower and higher committees of political parties in the country and smothers them. Victory of the executive would help destroy democracy by reinforcing monolithic control and terrorising dissident elements to submit to their party leaders.

(2) Too great an obsession with negative aspects of discipline ruins the structure of positive discipline and impairs the fabric of negative discipline as well because:—

(a) no effort is made to ensure the positive discipline of money flowing from the bottom to the top and the party of socialism is weakened through the split mind of wanting to take the votes of the poor with the money of the rich ;

(b) no effort is made to organise meetings of constituency committees and primary units. Under the constitution, primary units must meet four times in the year and constituency committees six times but sacialist lehdership is continually violating this requirement of discipline and the constitution ;

(c) no effort is made to change over fro mherd membership to human members. Leadership money, somnolent committees and cattle membership make impossible the rise of mass consciousness ;

(d) crude personalism prevails in the shape of leaders wanting to have their nominees selected as assembly and parliament candidates. Leaders adjust their claims with one another according to their importance and, if anybody refuses to fall in with this

personalism and wants to encourage collective decisions by appropriate committees, he is denounced as an individualist by the wolf-pack of leaders.

(e) premium is put on the virtues of 'nam-jap' and chorussing and action and thought are discouraged ;

(f) no disciplinary action was ever taken even in regard to negative discipline such as continuance in the I. N. T. U. C. or similarly unfriendly bodies or speaches in parliaments contrary to accepted policies of rationalisation, linguistic states and the like ;

(g) no disciplinary action was ever contemplated, not even warning issued, against accredited representatives of the party who had made public promise of coalition with the congress party in the event of acceptance of their terms. They had sought coalition, while the congress party had only sought co-operation ;

(h) those who would like to encourage talk and ban abuse are the greatest vilifiers, for they mistake their opponents' talk for abuse and their own abuse for legitimate talk. I accuse the entire socialist top of making personal and malicious attacks on our motives and in writing, while I would challenge them to produce a single written sentence from me attacking any individual and his motives. I have never asked for action against them, nor would I do so in future, for harsh words may be a cause of disapproval but never of legal action.

(3) Faulty notions of discipline and democracy cover up the socialist leadership's uttar failure in the triple spheres of action, thought and organisation, because:—

(a) the latest disclosures made by the Andhra Secretary and the all-India Chairman of the Party reveal that a meeting had been sought and arranged with the Andhra Congress chief for an alectoral adjustment. Such a flagrant violation of Party policy is directly due to the pro-Congress temper and is pro-

bably continually taking place in secret. The only point still in dispute in these disclosures is whether the Andhra Secretary was the initiator and the all-India officers accomplices or the all-India officers initiators the Andhra Secretary a deft cancellor of this most offensive violation of party policy ;

(b) between April and September, 1954, people's temper in U. P. was warming up with inevitable repercussions throughout the country, so that a nation-wide struggle against misery would have started in the beginning of 1955. The narrowly administrative and non-human angle on police-firing adopted by the socialist leadership not only brought infamy to the socialist organisation without any profit but also effectively scotched all possibilities of a nation-wide awakening ;

(c) four-fold ideas of merger, coalition, coalition on terms and co-operation, each succeeding idea is more dangerous because it looks more innocent, are effectively paralysing the Party of Socialism. Debate on future intentions must not be allowed to obscure present behaviour ; persons guilty of spreading present paralysis may in fact swear by theoretical radicalism and party's policies ;

(d) Parliament has become an old harridan ever waiting on the smile of its prince-charming, the Prime Minister. Unemployment, ejectment, price disparities and injustices, are there but nothing rouses a people's movement. No political party prepares a national struggle against injustice. Individual civil disobedience is discouraged. The Praja Socialist Party must become active on all these fronts of Parliamentary opposition, peoples movements, mass struggles and individual civil disobedience, before it can be called an opposition party of an effective party.

In particular, I should like to pay my tribute to the Dehri Dalmianager constituency Praja Socialist Party for passing resolutions at committee sessions as well as

a public meeting attended by several thousand persons asking for removal of the dictatorial National Executive. Every constituency committee in the country must meet debate and pass resolutions. This will be a powerful beginning towards people's participation in politics. Furthermore, the party of socialism in Blhar, perhaps the best unit in the country as far as its rank and file and its grass-roots organisation are concerned, has been turned into a stronghold of reaction over the past few years by an incompetent leadership. The stronghold is crumbling rapidly and the Bihar Party may perform an astonishing double-march. If that happens, there is some hope yet of the Praja Socialist Party reforming throughout the country and beginning on a new phase of its career particularly after the next National Conference.